HP/129/SML/2019-2021

Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500

01-15 मार्च, 2020

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2, अंक 40/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

मनुष्य का वर्तमान स्वरूप उसके विचारों की अभिव्यक्ति है .... डॉ॰ एल सी शर्मा

THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SDG's GOALS

श्रीमद्भगवत गीता का ई -संस्करण तैयार करेगा आईआईआरडी

ई लर्निंग से लोगों तक गीतासार पहुंचाने की कवायद शुरु

अंजना ठाकुर, कुरूक्षेत्र

आईआईआरडी शिमला की ओर से जल्द ही श्रीमद्भगवत गीता का ई-लर्निंग संस्करण लॉच किया जाएगा। इसके तहत जहां लोग गीता का ज्ञान ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे वहीं हर माह में निर्धारित दिन पर गीता उपदेशों का प्रसारण भी किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे ही गीता के उपदेशों को सुन सके। श्रीमद् भगवत गीता का ई संस्करण तैयार करने की घोषणा आईआईआरडी शिमला के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कुरूक्षेत्र में आयोजित एक समारोह के के दौरान दी। आईआईआरडी की ओर से कुरूक्षेत्र में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम और वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में आईआईआरडी के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आगाज संस्था के चेयरमैन प्रो आर. के. गुप्ता ने संस्था के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दीप प्रजवल्लित कर किया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रो. आरके गुप्ता ने मानव जीवन में श्रीमद्भगवत गीता के ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का सारगर्भित रूप प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य को कर्म यानी अपना कार्य करना चाहिए, इसमें कहीं भी फल की इच्छा बाधा नहीं बननी चाहिए।

प्रबंध निदेशक डाक्टर एल. सी. शर्मा ने सभी अतिथियों और संस्था से जुड़े सदस्यों का कार्यक्रम में स्वागत किया। उन्होंने सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा की कुरूक्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य संस्था से जुड़े सदस्यों को श्रीमद्भगवद गीता के मानव जीवन में महत्व से रूबरू कराना था। उन्होंने कहा कि आईआईआरडी जल्द ही श्रीमद्भगवत गीता का ई-लर्निंग संस्करण तैयार करने जा रही है। इसे ऑडियो, विडियो दोनों ही फार्मेट में तैयार किया जाएगा और साथ ही निर्धारित दिन पर इसका प्रसारण भी किया जाएगा।

इस मौके पर आईआईआरडी निदेशक ब्रिगेडियर बी के खन्ना, निदेशक सुषमा शर्मा, सह निदेशक रविकांत वावगे, कंपनी सचिव अभिमन्यु कवंर, आनन्द नायर सीईओ फ्लायर ग्रुप, डॉ० के आर शांडिल रीव क्लीनिक, रंजन मोहंती सीईओ आईएफटीआई, दीपक पंड्या नवनियुक्त निदेशक आईएफएसडी, अजय वशिष्ठ, नीना खन्ना कंस्लटेंट, विवेक दंडवते प्रमुख आर्किटेक्ट कंस्लटेंट, अमित श्रीवास्तव राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश, नरेंद्र राठौर सेंटर हैड डीडीयूजीकेवाई उत्तराखंड समेत आईआईआरडी के विभिन्न प्रभागों के सदस्य मौजूद रहे।

काम को अधिकार समझ कर करें

व्यक्ति को हमेशा गीता के उपदेश का अनुसरण करते हुए बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए। इतना ही नहीं हम जो भी काम करते हैं उसे अपना अधिकार समझ कर करना चाहिए। जिस तरह हम अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहकर उसका हनन नहीं होने देते और उसके लिए हमेशा सजग रहते हैं, ठीक उसी तरह की भावना व्यक्ति को अपने काम के प्रति भी रखनी चाहिए।

प्रो. आरके गुप्ता, चेयरमैन आईआईआरडी

विकास के लिए आपसी मेलजोल और भरोसा बेहद ज़रुरी

जब भी हम किसी काम को बतौर मिशन उस पर मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाना आसान हो जाता है। बड़े काम को करने के लिए आपसी मेलजोल और एक दूसरे पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। यह मंत्र व्यवसायिक सफलता के साथ ही सामाजिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी जरूरी है।

ब्रिगेडियर बीके खन्ना, निदेशक आईआईआरडी

रीता वर्मा बनी इम्पलॉय ऑफ दी ईयर

आईआईआरडी में पिछले पांच सालों से बतौर एडमिन एसोसिएट कार्यरत रीता वर्मा को इंम्पलाई ऑफ दी ईयर चुना गया। रीता वर्मा के नाम की घोषणा भी कुरूक्षेत्र में आयोजित वार्षिक बैठक के दौरान की गई। उल्लेखनीय है कि आईआईआरडी की ओर से हर साल किसी एक कर्मचारी को बेहतरीन कार्यप्रदर्शन करने के लिए इम्पलाई ऑफ दी ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसमें ट्रॉफी के साथ ही प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार राशि भी कर्मचारी को प्रदान की जाती है। इम्पलाई ऑफ दी ईयर बनने के बाद रीता वर्मा ने संस्था के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें सम्मान पाने पर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आईआईआरडी में काम करते हुए उन्हें हमेशा ही ऐसा लगा जैसे वह अपने परिवार के सदस्यों के बीच काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां महिला पुरूष को काम करने के समान अवसर दिए जाते हैं।

कुरुक्षेत्र में आईआईआरडी ने तय किया विज़न 2020

देश भर में सेवाक्षेत्र में तैयार हुआ योजना का ख़ाका

हेम राज चौहान, कुरूक्षेत्र

आईआईआरडी का इस वित्तिय वर्ष 2020 के लिए विकास का ख़ाका कुरूक्षेत्र में वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया गया जिसमें देश भर से आईआईआरडी से संबद्ध समस्त सेवाकर्मियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । बैठक में संस्था से जुड़े समस्त विभागों द्वारा इस वित्तिय वर्ष के लिए दी जाने वाली सेवाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें विगत वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ इस वर्ष के लिए किस प्रकार सेवाऐं प्रदान की जाऐंगी, इसका डिजिटल प्रस्तुतिकरण कर प्रबन्धन को सौंपा गया ।

इस अवसर पर प्रबन्धन की ओर से चेयरमैन प्रो. आर के गुप्ता, प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा, निदेशक ब्रिगेडियर बी के खन्ना, निदेशक सुषमा शर्मा के अलावा वरिष्ठ सहयोगी और अन्यों ने प्रतिभागिता दी । आईआईआरडी वर्तमान में देश भर के 22 से अधिक राज्यों में अपनी पदछाप छोड़ चुका है और सीएसआर, मिशन रीव तथा सरकार की अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों में एक तकनीकि संस्था के रुप में बेहतर प्रदर्शन के साथ सेवाऐं प्रदान कर रहा है । इसी के तहत संस्था से संबद्ध विभिन्न विभाग भी अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाकर योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में अव्वल है । कुरुक्षेत्र में आयोजित वार्षिक बैठक में इन्हीं संबद्ध विभागों ने अपनी योजनाओं की प्रस्तुति देकर प्रबंधन को अवगत करवाया । इसमें तकनीकि स्तर पर बेहतरीन सेवाऐं दे रही आईएफटीआई, डीडीयूजीकेवाई, यूपीएसडीएम, मिशन रीव, रीव क्लिनिक, फ्लायर ग्रुप, आईएफएसडी, एचपीकेवीएन, पीएमकेवीवाई आदि संबद्ध विभागों द्वारा अपनी योजना का डिजिटल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देशभर में किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, आदि राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में हुए कार्यों एवं आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई तथा गुणवत्ता आधारित सेवाओं की निरंतरता हेतु आवश्यक क़दमों की समीक्षा भी की गई।

आईआईआरडी सामाजिक मुद्दों और विकास के मॉडल के रुप में देश भर में अद्वितीय प्रयासों के साथ सेवाओं हेतु संकल्पबद्ध है ।

आईआईआरडी ने की नियुक्ति दीपक पंड्या बने आईएफएसडी के निदेशक

आईआईआरडी से संबद्ध आईएफएसडी के नए निदेशक दीपक पंड्या होंगे । प्रबंधन ने इस नियुक्ति पर मुहर लगा दी है । दीपक पंड्या इससे पूर्व सीएसआर में देश-विदेश में सेवाऐं दे चुके हैं तथा सीएसआर में प्रकाशन का कार्य भी देख चुके हैं । मिशन ज़ीरो सूसाईड यानि आत्महत्या निवारण में भी देश-विदेशों में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते रहे हैं । सीएसआर में ही स्नातकोत्तर दीपक पंड्या परामर्शदाता के रुप में भी सेवाऐं देते रहे हैं ।

कुरुक्षेत्र में धार्मिक विरासत से रुबरु हुआ आईआईआरडी परिवार

अंजना ठाकुर, कुरूक्षेत्र

आईआईआरडी की ओर से स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम के सभी सदस्यों ने संस्था के चेयरमैन प्रो. आर के गुप्ता और प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा की अगुवाई में कुरूक्षेत्र स्थित सभी तीर्थस्थानों की यात्रा की। यात्रा के दौरान सबसे पहले टीम आईआईआरडी कुरूक्षेत्र स्थित भद्रकाली मन्दिर पहुंची। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद स्थानेश्वर महादेव, ज्योतिसर में भी दर्शन किए।

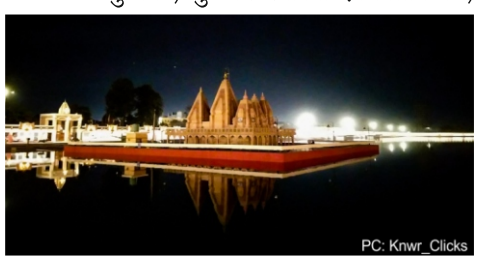

ज्योतिसर वह स्थान है जहां श्रीकृष्ण ने अर्जुन को विराट में दर्शन दिए थे और गीता का ज्ञान दिया था। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिन्दू तीर्थ है। ज्योति का अर्थ प्रकाश है तथा सर का अर्थ तालाब। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और यहीं अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। यहीं पर आईआईआरडी टीम के सदस्यों ने लेजर लाइट तकनीक पर आधारित गीतासार के डिजीटल फिल्मांकन के माध्यम से अर्जुन और श्रीकृष्ण के मध्य संवाद का ज्ञान भी प्राप्त किया। इसके साथ ही भीष्मकुंड, कुरूक्षेत्र गुरूद्वारा, तारामंडल, श्रीकृष्ण म्युजियम, कुरूक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र, ब्रह्म सरोवर की भी यात्रा की। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य आईआईआरडी परिवार के सदस्यों को भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत से रूबरू कराना था।

शिक्षा सुधार में हिमाचल की बड़ी छलांग, देश भर में मिला छठा रैंक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा सुधार में बड़ी छलांग लगाई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी हुए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018–19 में हिमाचल ने 1000 में से 799 अंक लेकर देश भर में छठा रैंक प्राप्त किया है। 2017–18 की रेटिंग में हिमाचल का 14वां रैंक था। इस दौरान प्रदेश को 1000 में से 736 अंक मिले थे। शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं, समान शिक्षा और गवर्नेंस प्रोसेस के मामले में हिमाचल ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने 70 बिंदुओं के पैमाने पर आधारित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) रिपोर्ट को 2018 से तैयार करने की शुरुआत की है। मंत्रालय ने इन बिंदुओं के आधार पर सभी राज्यों से ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इस सूचना के आधार पर 2018–19 की रिपोर्ट तैयार हुई है। राज्यों की शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन को सात ग्रेड में विभाजित किया था, जो कि शून्य से 1000 वेटेज पर आधारित था। लेवल वन और टू में कोई राज्य शामिल नहीं हो सका है। किसी भी राज्य की परफॉर्मेंस 901–1000 नंबरों के मानकों को पूरी नहीं कर सकी। चंडीगढ़, गुजरात और केरल को लेवल थ्री 851–900 का वेटेज और ग्रेड एक प्लस की श्रेणी मिली है। महाराष्ट्र और दिल्ली को लेवल फोर 801–850 का वेटेज और ग्रेड एक की श्रेणी मिली है।

हिमाचल, हरियाणा व पंजाब को 751–800 वेटेज के साथ ग्रेड दो मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षकों, प्राचार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण की कमी, शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण, वित्त की समय पर उपलब्धता के मुद्दे शिक्षा प्रणाली को विफल करने वाले कारक हैं।

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चौथी से नौवीं कक्षा तक बदला पाठ्यक्रम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए चौथी से नौवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इन कक्षाओं के लिए पुराने अध्याय हटाकर कुछ नए अध्याय जोड़े गए हैं। बोर्ड ने प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में एनसीईआरटी दिल्ली से प्राप्त प्रकाशनाधिकार के अनुसार संशोधन किया है। इसके तहत चौथी कक्षा की मारिगोल्ड किताब के यूनिट-6 के तीनों अध्याय नहीं पढ़ाए जाएंगे। पांचवीं कक्षा में भी मारिगोल्ड किताब के यूनिट नौ का अध्याय 'लेशन अराउंड द वर्ल्ड' को हटाया गया है। छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान किताब से आरंभिक मानव की खोज व भोजन संग्रह से उत्पादन तक दो अध्यायों के स्थान पर आखेट-खाद्य संग्रह से भोजन तक शामिल किया है।

सातवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन-11 में से इकाई चार के अध्याय सात 'विज्ञापनों को समझना' नहीं पढ़ाया जाएगा, जबकि इसी कक्षा की हमारा पर्यावरण किताब से अध्याय नौ 'शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन' हटाया गया है। आठवीं कक्षा की 'इट सो हैपन' में नया अध्याय-11 'एनसिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया' शामिल किया गया है। नौवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति-एक के अध्याय एक समकालीन विश्व में लोकतंत्र नहीं पढ़ाया जाएगा। आठवीं कक्षा की वसंत पुस्तक में नया अध्याय-19 'खुली चिट्ठी' को शामिल किया है। इस अध्याय के जरिए छात्र नशे से आर्थिक और शारीरिक दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही नशे के सेवन से गंभीर बीमारियों के बारे में भी बताया जाएगा।

बजट – 2020 : आईटी शिक्षकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, जलवाहकों को भी तोहफा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। सीएम ने 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। तेरहवीं विधानसभा के इस बजट सत्र में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की ।

बजट की घोषणाएं

- 20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाने का प्रस्ताव।
- आईएचबीटी ने हींग की नई प्रजाति की पहचान की है। इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केसर उत्पादन पर भी फोकस किया जाएगा।
- कृषि संपन्नता योजना की घोषणा।
- 2020–21 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे। दो रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाने की घोषणा।
- 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
- पर्वत धारा योजना की घोषणा। इससे भू-जल स्त्रातों का संरक्षण होगा।
- ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा।
- 500 रुपये चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।
- नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्याल बनाने की घोषणा। नौ करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य।
- आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
- जलवाहक छह साल की बजाय अब पांच साल में नियमित होंगे।
- मिड-डे मील वर्करों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा।
- दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक एक लाख रुपये देने की घोषणा।
- क्लस्टर विवि मंडी में आसपास के कॉलेजों को शामिल किया जाएगा।
- आशा वर्कर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
- 60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आर्युवेदिक दवाइयां दी जाएंगी।
- शिमला में गंज बाजार अनाज मंडी को टूटीकंडी में स्थापित किया जाएगा।
- भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा।
- राजस्व विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये मासिक और नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
- युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020–21 में नौ रोज़गार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
- प्रदेश में 2020–21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

हिमाचल लोकसेवा आयोग ने रोकी स्कूल प्रवक्ता भर्ती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में स्कूल प्रवक्ता की परीक्षाएं लेने के विवाद के बाद लोकसेवा आयोग ने आगामी आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद राज्य लोकसेवा आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय के पाले में गेंद डाल कर इसी सप्ताह स्पष्टीकरण देने को कहा है। आयोग की सचिव ने कहा है कि शिक्षा निदेशालय के जवाब के बाद आगामी परीक्षाओं का भविष्य तय होगा।

कामर्स की परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लेने से यह विवाद खड़ा हुआ। लोकसेवा आयोग के कार्यालय पहुंच कर कुछ अभ्यर्थियों ने कामर्स परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षाएं लेने की मांग की। इसी बीच आयोग ने आननफानन में 14 मार्च को होने वाला राजनीति शास्त्र का पेपर भी अंग्रेजी में लेने का आदेश जारी कर बात बिगाड़ दी।

अब मामला तूल पकड़ने पर आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर स्कूल प्रवक्ता भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट करने और आरएंडपी नियम संशोधित

करने को कहा है। आयोग की सचिव राखिल काहलो ने बताया कि आगामी परीक्षाएं निदेशालय के स्पष्टीकरण के बाद ही होंगी। आवेदकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी ।

बजट सत्र में बोले सीएम जयराम अब प्रदेश में नहीं दिया जाएगा सेवा विस्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में अब पुनः रोजगार और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

आने वाले समय में इस मसले को गंभीरता से देखा जाएगा।

कोरोनावायरस : हाई रिस्क वाले 11 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगा तो भारत में भी द. कोरिया, ईरान, इटली जैसे हो सकते हैं हालात ?

- **दुनिया के 67 देशों में अब तक आ चुके हैं कोरोनावायरस के मामले, 11 देशों में मौतें हुई हैं**
- **कोरिया, ईरान और इटली में कोरोना तेजी से इसलिए फैला, क्योंकि सरकारों ने शुरु में यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए**
- **सरकार ने चीन और ईरान से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, देश में जो दो नए केस है, दोनों व्यक्ति इटली, ब्रिटेन और दुबई की यात्रा कर आए**

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोरोनावायरस के भारत में और नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। यह केस दिल्ली और तेलंगाना में सामने आए हैं। दिल्ली में जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वह इटली और ब्रिटेन से यात्रा करके आया है, जबकि तेलंगाना केस में व्यक्ति दुबई से लौटा है। ऐसे में यदि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता नहीं बरती तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। सरकार ने कोरोनावायरस से प्रभावित कई देशों से यात्रा पर अभी तक रोक नहीं लगाई है। वीजा और ई-वीजा पर रोक भी नहीं लगाई। जबकि दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान जैसे देश इसके नतीजे भुगत रहे हैं, इन देशों ने भी कोरोनावायरस के शुरुआती मामले सामने आने के बाद चीन और अन्य देशों के साथ यात्रा पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में जब प्रतिबंध लगाए, तब तक स्थिति गंभीर हो गई।

दुनिया के 67 देशों में अब तक कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं। इनमें से 11 देशों में कोरोनावायरस से मौतें हो चुकी हैं। चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया में यात्रा करना जोखिम भरा है। यहां यात्रा न करने की चेतावनी जारी हो चुकी है। जापान और हॉन्गकॉन्ग में यात्रा करने से पहले विचार करने की चेतावनी है।

- **एडवाइजरी में कहा– 11 देशों की यात्रा से आने वाले हर एक व्यक्ति की हो स्क्रीनिंग**
- **देश के 21 एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर यात्रियों की जा रही है स्क्रीनिंग**
- **सरकार ने 5 देशों की यात्रा न करने को कहा है**

विधानसभा सत्र: सीएम जयराम बोले पूर्व सरकार से 1100 करोड़ कम कर्ज लिया हमने

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि सरकार काम कर रही है और विपक्ष नकारने में लगा है । पूर्व सरकार से 1100 करोड़ रुपये कम वर्तमान सरकार ने कर्ज लिए हैं। राज्य में आपराधिक मामले घटे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता में है। पर्यटन के दृष्टिगत शिमला और कांगड़ा हवाई पट्टी विस्तार प्राथमिकता में है। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने दूसरी बार सदन से वाकआउट कर दिया ।

सीएम ने सदन में जानकारी दी कि मंडी हवाई अड्डे के लिए जमीन तलाश ली है और सर्वेक्षण की राशि केंद्र सरकार को दे दी है । मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया गया । मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 से 10 साल पुरानी शिकायतों को निपटाया गया । कुल 33,200 शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं ।

सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत कुल 5 लाख हेल्थ कार्ड बनाए गए । एक साल में प्रदेश के 60 हजार लोगों का उपचार किया और 65 करोड़ खर्च किए। सरकार ने 189 जनमंच प्रदेश भर में कराए गए और कुल 45,704 शिकायतें में से 41,698 निपटाईं। कुल 2.76 लाख रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए । 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

नेपाल में कोरोना वायरस से हिमाचल के लाहौल में खौफ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पड़ोसी देश नेपाल में कोरोना वायरस के मामले सामने आने पर लाहौल में खौफ है । हालांकि अभी रोहतांग दर्रा से वाहनों की आवाजाही को नहीं खोला गया है। कई नेपाली ऐसे हैं जिन्होंने लाहौल घाटी के लोगों की जमीन लीज पर पहले से ही ले रखी हैं। ऐसे में नेपाली मौसम खुलने पर सीधे नेपाल से यहां खेतीबाडी करने के लिए पहुंच जाते हैं। लाहौल के लोगों ने नेपाल से आने वाले हर शख्स का मेडिकल चेकअप करवाने के अपील की है।

रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने से पहले ही कदमताल कर भारी संख्या में नेपाली मजदूरी को यहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं। करीब 30 फीसदी के नेपालियों ने यहां जमीन लीज पर ले रखी है। जिसमें कमाई की आधी रकम वह जमीन मालिक को देते हैं। ऐसे में एक ओर जहां नेपाली लोगों को लाहौल पहुंचने की उत्सुकता रहती है तो वहीं घाटी के लोगों में भी इनके यहां पहुंचने का बेसब्री से इंतजार रहता है।

नहीं सताएगी मोबाइल नेटवर्क की समस्या, शौचालयों पर लगाये जाएंगे टावर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शहर में अब लोगों को मोबाइल फोन में सिग्नल की समस्या नहीं सताएगी । नगर निगम शिमला शहर में बने सार्वजनिक शौचालयों पर मोबाइल टावर लगाएगा । इससे यहां पर लोगों को मोबाइल फोन का बढ़िया सिग्नल मिलेगा । इससे लोगों को बात करने में अब नेटवर्क की समस्या नहीं सताएगी । हरियाणा की कंपनी ने निगम को पत्र लिखकर जगह के लिए आवेदन किया था। कंपनी टावर लगाने के साथ निगम को इसके लिए किराया भी देगा। इससे निगम को सालाना करोड़ों रुपये की आय होगी। हालांकि अभी किराया तय नहीं किया है। कंपनी के साथ समझौते के दौरान ही किराये की दरें तय की जाएंगी ।

निगम ने शहरभर में बने 69 शौचालयों को टावर लगाने के लिए चिंह्नित किया है। इसके अलावा तीन पार्किंग जिनमें आइएसबीटी, बाईपास व सचदेवा पार्किंग में भी टावर लगाने प्रस्तावित किए गए हैं। टावर की ऊंचाई नौ मीटर होगी और यह टावर आसपास के क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करेगा। यहां पर मोबाइल टावर लगने से लोगों को भी काफी राहत मिलेगी।

कोरोना वायरसः आईजीएमसी में दाखिल मरीज के टैस्ट को भेजे सेंपल की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के बिलासपुर से आईजीएमसी शिमला लाए गए कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के लिए गए स्वाइन फ्लू से संबंधित सैंपलों की ऑनलाइन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि कोरोना वायरस से संबंधित सैंपलों की रिपोर्ट एम्स से दो से तीन दिन में आएगी। इसकी पुष्टि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जनक राज ने की।

वार्ड के अंदर सिर्फ टीम को जाने के आदेश

जिस वार्ड में मरीज को रखा गया है, उस वार्ड की मंजिल पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है प्रशिक्षित टीम मरीज की देखभाल कर रही है।

संदिग्ध मरीज आने पर आईजीएमसी चौकस, एंबुलेंस और स्टाफ तैनात

कोरोना का संदिग्ध मरीज आने के बाद आईजीएमसी प्रबंधन चौकस हो गया है। कोरोना वार्ड में उन्हीं चिकित्सकों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जिन्हें कोरोना से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना के लिए स्पेशल एंबुलेंस 104 तैनात की गई है।

लाहौल स्पीति, चंबा सहित प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी, रोहतांग में 1 फुट जमी बर्फ, आगे भी मौसम खराब रहने की आशंका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। ख़बर लिखे जाने तक लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले और चंबा के लक्कड़मंडी के पास जमकर बर्फबारी हुई । वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ है । बीआरओ की ओर से रोहतांग दर्रा के रास्ते से बर्फ हटाने के काम में भी बाधा पहुंची है। प्रशासन की ओर से सैलानियों से अपील की गई है कि वे बर्फबारी और बारिश वाले इलाकों में न जाएं।

रोहतांग में 1 फिट ताजा बर्फबारी हुई

रोहतांग में करीब 1 फुट बर्फबारी हुई है

जबकि केलांग में एक इंच, कोखसर में 2 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में बादल छाए हुए है और ठंडी हवाऐं चल रही है।

हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय इतने फीसदी बढ़ी, विकास दर गिरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय हर साल की तरह इस बार भी बढ़ गई है, जबकि आर्थिक विकास दर घट गई है। विकास दर पिछले साल के 7.1 से गिरकर 5.6 फीसदी पर पहुंच गई है । हालांकि, यह राष्ट्रीय विकास दर से थोड़ी ज्यादा है । राष्ट्रीय स्तर पर यह 5 प्रतिशत अनुमानित है। ऐसा वैश्विक मंदी के हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के चलते हुआ है। हालांकि, प्रतिव्यक्ति आय 1,95,255 रुपये वार्षिक हो गई है। इसमें भी आर्थिक मंदी के कारण 6.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 11 प्रतिशत थी ।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 प्रस्तुत किया । हिमाचल में वर्तमान कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय 2018–19 के लिए पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार 1,83,108 रुपये थी। वर्ष 2019–20 में इसके 1,95,255 रुपये होने के आसार हैं। वर्ष 2017–18 में प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 1,65,025 थी। आर्थिक विकास दर की बात करें तो यह जहां 2017–18 में 6.8 प्रतिशत थी, वहीं 2018–19 में 7.1 हो गई थी। वर्ष 2019–20 में यह घटकर 5.6 फीसदी तक ।

शिमला में महसूस किए गए कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके

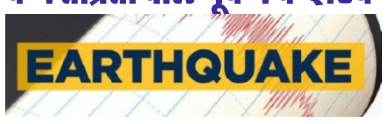

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में रविवार की सुबह करीब 10 बजकर 13 मिनट पर कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केन्द्र शिमला में जमीन के नीचे पांच किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था।

फोरलेन के लिए कटेंगे हजारों पेड़

सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एनएचएआई ने शुरु की कवायद, वन विभाग काटेगा पेड़

देवदार, चील, बान और कायल के पेड़ कटेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कालका-शिमला फोरलेन के कैथलीघाट से ढली तक के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने फोरलेन के लिए करीब एक हजार 60 पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है। यह सभी पेड़ निजी भूमि पर हैं। 31 मार्च तक इन पेड़ों को काटने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही सरकार ने हरकत में आकर पेड़ों को काटने को मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेड़ों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। एनएचएआई ने इन पेड़ों को काटने का जिम्मा वन विभाग को सौंपा है। अब वन विभाग छकड़ैल से लेकर ढली तक इन पेड़ों को निजी भूमि से हटाएगा। इसमें देवदार, चील, बान, कायल, ककर और पाजा के अलावा कई अन्य प्रजातियों के पेड़

शामिल हैं। कैथलीघाट से ढली तक के फोरलेन निर्माण का काम कर रही कंपनी ने फोरलेन के भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं होने का हवाले देते हुए कई महीने से निर्माण कार्य बंद कर रखा है। अब सरकार से इन पेड़ों को काटने की मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे फोरलेन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

तीन चरणों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

तीन चरणों में लागत के हिसाब से यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले चरण में कालका-सोलन, दूसरे चरण में सोलन-कैथलीघाट के बाद कैथलीघाट-ढली फोरलेन है। तीसरे चरण के करीब 27 किलोमीटर के इस फोरलेन में विश्वस्तरीय फ्लाईओवर, ब्रिज और टनलों का निर्माण होना है।

द रीव टाइम्स ने उठाया था यह मुद्दा..

हज़ारों पेड़ कटने पर सरकार ने एक भी पेड़ नहीं लगाया था

आरटी आई में हुआ था खुलासा

द रीव टाइम्स ने इस मुद्दे की पोल खोली थी जब आरटीआई में यह खुलासा किया था कि हज़ारों पेड़ों की बलि इस फोर लेन के लिए दी जा चुकी है और इसके एवज़ में सरकार ने एक भी पेड़ लैंड बैंक न मिल पाने का कारण बताते हुए नहीं लगाया था । एनएचएआई के लाखों रुपये वन विभाग के खाते में इसके लिए जमा है लेकिन सरकार लैंड बैंक ही ढूंढ रहा है ।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

नहीं मानते माननीय...

बजट सत्र में विधानसभा के सदन में मोबाइल लाने पर रोक...

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश के बाद स्टेट सीआईडी ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान कोई भी सदस्य मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

हर सत्र से पहले इस तरह की वेरीफिकेशन जारी होती है, लेकिन विधायक उन आदेशों का पालन नहीं करते। पूर्व में भी पक्ष और विपक्ष गैलरी में बैठे कोई न कोई सदस्य मोबाइल का प्रयोग करते दिखे हैं। अक्सर देखा गया है कि सदन की कार्यवाही के दौरान अधिकांश विधायक मोबाइल पर चौट करने से कोई गुरेज नहीं करते।

इसे देखते हुए विधानसभा सचिवालय ने सदन के भीतर मोबाइल पर रोक लगा दी है। 25 फरवरी से एक अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सदन में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। सत्र शुरू होने से पहले विस सचिवालय ने कई अहम नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही और स्थगन से पहले सभी विधायकों को हाजिरी लगानी होगी।

शहर में एक साथ नगर निगम बढ़ा रहा है टैक्स, गारबेज शुल्क और पेयजल बिल

राजधानी में छह साल बाद बढ़ रहा है टैक्स, पेयजल दरें और कूड़ा शुल्क में दस फीसदी होगी बढ़ोतरी

हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बढ़ी दरों का असर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रापर्टी टैक्स, पेयजल बिल और कूड़ा शुल्क चुकाने के लिए शहरवासियों को अगले महीने से अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी। पहली बार टैक्स, बिल और गारबेज शुल्क में एकसाथ बढ़ोतरी होने जा रही है। नगर निगम पेयजल दरें और कूड़ा शुल्क तो हर साल दस फीसदी बढ़ाता ही है, लेकिन इस बार प्रापर्टी टैक्स में भी दस फीसदी बढ़ोतरी का फैसला लिया है।

कूड़ा शुल्क में होने वाली दस फीसदी बढ़ोतरी तो लागू भी कर दी है। कूड़ा शुल्क के ऑनलाइन साफ्टवेयर में दस फीसदी बढ़ी दरों पर शुल्क वसूले जा रहे हैं। यदि कोई उपभोक्ता अगले तीन या छह महीने का एकसाथ बिल भर रहा है तो उसे अप्रैल से बढ़ी दरों के अनुसार बिल जारी हो रहा है। प्रापर्टी टैक्स में छह साल बाद नगर निगम इजाफा कर रहा है। शहर में कुल साढ़े 28 हजार

भवन मालिक हैं जिनसे नगर निगम करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स वसूलता है। टैक्स बढ़ने से निगम की आय करीब 15 करोड़ हो जाएगी। नगर निगम अप्रैल से टैक्स के नये बिल जारी करना शुरू कर देगा। नगर निगम शिमला ने आय में बढ़ौतरी के लिए आम शहरी पर ही बोझ डालने की तैयारी कर ली है । किसी भी प्रकार की राहत न देते हुए इस प्रकार की मनमानी बढ़ौतरी से लोगों में खासा रोष है । लोगों ने इस का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि निगम ने जनता को पीसना शुरु कर दिया है ।

सीएम बोले, 30 हजार को मिली सरकारी नौकरीयां , योग शिक्षकों की भर्ती होगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने में देश में नंबर एक पर है । यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के प्रश्न पर कही । उन्होंने सदन को बताया कि 3 वर्षों के दौरान 30574 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है । आउटसोर्स भर्ती अन्य राज्यों में भी हो रही है।

चाहे वह कांग्रेस शासित राज्य हैं या भाजपा शासित प्रदेश, सभी में आउटसोर्स पर नौकरियां दी जा रही हैं। अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को 2 वर्ष के अंदर नियमित करने को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह विचाराधीन है। इससे पूर्व राजेंद्र राणा ने बात उठाई कि भाजपा के दृष्टि पत्र में उसे शामिल किया गया था। सीएम जयराम ठाकुर ने सेवा विस्तार पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अब प्रदेश में किसी को भी सेवा विस्तार न देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा पूर्व सरकार के समय सबसे ज्यादा सेवा विस्तार दिया गया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सहकारी सभा घोटाला: खाताधारकों का चक्का जाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

विस क्षेत्र गगरेट के बहुचर्चित दियोली सहकारी सभा के 11.70 करोड़ के घोटाले की चिंगारी फिर सुलग गई है। अमानत राशि न मिलने से गुस्साए खाताधारकों ने हाल ही में दौलतपुर चौक-गगरेट मुख्य मार्ग पर धरना दे दिया। इससे पहले खाताधारकों ने दियोली सहकारी सभा के प्रधान सुरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में सभा के सामने सड़क पर यातायात बाधित कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और विजिलेंस जांच की मांग के साथ नारेबाजी की। उन्होंने अपने जमाधन को शीघ्रातिशीघ्र वापस करने की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी हरनाम सिंह ने धरने पर बैठे लोगों को

समझाया। उनकी मांग के अनुसार एसपी कार्यालय से दियोली सहकारी सभा की जांच विजिलेंस को सौंप दी। उन्होंने खाताधारकों को बताया कि अगर 15 दिन के अंदर इस बाबत कार्रवाई नहीं होती, तो खाताधारक रोष व्यक्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सभा के खाताधारकों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जांच में कोई तेजी न होने की वजह से मजबूरन लोगों ने सड़क पर उतरकर धरना दिया। दियोली सहकारी सभा के करीब 1800 खाताधारक हैं। इनकी सभी में 11.70 करोड़ की पूंजी फंस गई है। सभा में जमा कमाई को वापस लेने की मांग को लेकर लगभग एक साल से खाताधारक लगातार सरकार के समक्ष मांग रख रहे हैं। खाताधारकों का आरोप है कि कोई भी सरकारी एजेंसी उनकी फरियाद नहीं सुन रही है। खाताधारकों ने स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस घोटाले की जांच को लेकर पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद मामले में जांच आगे नहीं बढ़ाई जा रही है।

शिक्षा में शून्य नवाचार पर सोलन के तीन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

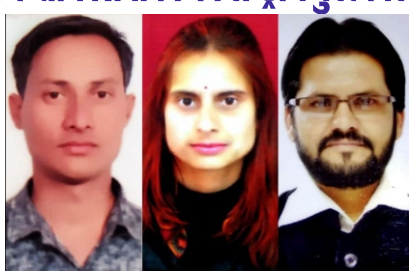

शिक्षा में शून्य नवाचार के लिए सोलन जिले के तीन प्राथमिक शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश दिल्ली में इन शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में शिक्षा खंड रामशहर के कपिल राघव, शिक्षा खंड धुंदन के दिलीप कुमार तथा शिक्षा खंड कंडाघाट की पूनम कश्यप शामिल हैं। शिक्षा में शून्य नवाचार के लिए 28 फरवरी से दो मार्च तक तक श्री अरविंदो सोसायटी की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक कार्यशाला में पूरे देश के सभी राज्यों से चयनित शिक्षकों के पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रत्येक राज्य के चयनित शिक्षकों के नवाचारों से निर्मित नवाचार पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में समस्त भारत के राज्यों के चयनित शिक्षकों ने भाग लिया।

साइकिल रेस से नशे के खिलाफ दिया संदेश, मिताली राज ने दिखाई हरी झंडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नशे के खिलाफ युवा को जागरूक करने के लिए ऊना में साइकिल रेस करवाई गई। क्रिकेटर मिताली राज ने साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई।

इंदिरा मैदान से दौड़ शुरू हुई। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेस में उपायुक्त ऊना संदीप कुमार, एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, एएसपी शमशेर सिंह सहित 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 80 किलोमीटर की दौड़ जोगीपंगा, रायपुर मैदान, भाखड़ा, नंगल होते हुए ऊना में संपन्न हुई।

सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। इससे पहले डीसी ने कहा कि रैली से नशे के विरुद्ध जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। वहीं फिट इंडिया का संदेश भी दिया गया।

उन्होंने कहा कि साइकिल रैली में पंजाब के भी कई प्रतिभागी शामिल होने के लिए आए जिन्हें साइकिलिंग के माध्यम से गोबिंद सागर झील की प्राकृतिक सुंदरता देखने का भी मौका मिला।

गोबिंद सागर झील के किनारे स्थित रायपुर मैदान का क्षेत्र बेहद खूबसूरत है और साइकिल रैली के माध्यम से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस दौरान जिला खेल अधिकारी एमपी भराड़िया भी मौजूद रहे।

माफिया तान रहा बंदूक, वन रक्षकों को हथियार तक नहीं दे पाई सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

कुटलैहड़ क्षेत्र में खैर तस्करी का अवैध कारोबार दिन-रात फल-फूल रहा है। क्षेत्र में वन काटुओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि खैर तस्करी के अवैध कारोबार को करने वाले लोग वन विभाग के अधिकारियों पर ही बंदूक तान कर भगाने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व बुधान पंचायत में हुए घटनाक्रम ने एक बार फिर से गार्ड होशियार सिंह की याद दिला दी। गनीमत रही कि बंदूकधारी वन काटुओं ने बंदूक में कारतूस लोड नहीं किए थे। वन माफिया वन विभाग के गार्ड और आरओ पर बंदूक तान कर खाली ट्रिगर चलाते रहे। विभाग के मुताबिक वन काटुओं ने शराब का सेवन किया था, जिस कारण विभाग के कर्मचारियों ने चार लोगों को दबोच लिया, जबकि एक भाग निकला। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार वन विभाग के कर्मियों को अभी तक हथियार उपलब्ध नहीं करवा पाई। लगता है कि प्रदेश सरकार किसी और होशियार सिंह मामले का इंतजार कर रही है।

गोलीकांड का मामला एक वर्ष पहले हरोली क्षेत्र में भी घटित हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इससे भी सबक नहीं लिया है। लोगों में रोष है कि इससे पहले भी क्षेत्र के जंगलों के हजारों पेड़ वन माफिया काट चुका है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इससे दिन प्रतिदिन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

लोगों में रोष है कि कई बड़े लोग भी इस धंधे में संलिप्त हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि अंबेहड़ा में पकड़े खैर कटान आरोपी पर पुलिस ने 72 घंटे बाद मामला दर्ज किया। लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वन काटुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए वन विभाग को हथियारों के साथ लैस किया जाए। क्षेत्र वासियों का आरोप है कि वन माफिया सरकारी जंगलों के साथ-साथ निजी भूमि से भी पेड़ काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हथियार प्रदान करे, जिससे कि विभाग के कर्मी हथियारों से लैस होकर सरकारी जंगलों का संरक्षण कर सके।

बंगाणा के लोगों को मिलेगी सीवरेज सुविधा: वीरेंद्र कंवर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बंगाणा और आसपास के इलाकों के लिए तीन वर्षों में सीवरेज सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बंगाणा में सीवरेज व्यवस्था के निर्माण के लिए 5.54 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। सीवरेज की सुविधा से बंगाणा उपमंडल की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि धनराशि मिलने के बाद जल शक्ति विभाग के अधिकारी अब सीवरेज सिस्टम के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे हैं। उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों के भीतर बंगाणा व आसपास के निवासियों को सीवरेज की सुविधा मिल पाएगी। बंगाणा सीवरेज सिस्टम में 110 चैंबर तथा 646 मैनहोल बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 400 केएलडी होगी। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम होने से गंदा मलयुक्त पानी सीधे नालियों के रास्ते नालों और आगे नदी तक तक नहीं पहुंचेगा। सीवरेज व्यवस्था होने से गंदे पानी का ट्रीटमेंट हो सकेगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी के हानिकारक केमिकल निकाल कर इसे दोबारा खड्ड में छोड़ दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल पाएगी और नदी-नालों का पानी दूषित होने से बच सकेगा। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ

माध्यमिक पाठशाला बंगाणा में 1.20 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान भवन बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बंगाणा में ही मिनी सचिवालय 19 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। साथ ही बंगाणा ब्लॉक के भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

सतौन बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश, 13 दुकानदारों के चालान

द रीव टाइम्स, सिरमौर

सतौन बाजार में हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से भाग खड़े हुए। जब कई दुकानें बंद मिलीं तो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से दुकानें खुलवाई गईं। इसके बाद दुकानदारों व ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. अतुल कायस्थ की अगुवाई में हुई छापामारी के दौरान विभाग ने कुल 13 दुकानों के चालान काटे। इनमें अधिकतर दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं थे। साथ ही स्वच्छता नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थीं। कई दुकानदार खुले में ही खाद्य वस्तुएं बेच रहे थे। लिहाजा, सहायक आयुक्त डॉ. अतुल कायस्थ ने दुकानदारों के साथ बैठक कर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकान पर बनी वस्तुओं को ढककर रखें। साथ ही दुकान के भीतर व आसपास सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सात दिन के भीतर सभी दुकानदारों के लाइसेंस बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद विभाग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा।

नक्शा पास कराने के लिए वार्ड मेंबर से लेना होगा एनओसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

नगर परिषद ऊना के तहत अब भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराने के लिए वार्ड मेंबर से भी एनओसी लेना होगा। ऊना तहसीलदार विजय राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में नप अध्यक्ष बाबा अमरजोत बेदी के अलावा वार्ड नंबर 2, 3, 4, 7, 8 तथा वार्ड नंबर 10 के पार्षद उपस्थित थे।

बैठक में 21 पेंशनरों के केस के अलावा कई भवनों के नक्शों को अनुमति दी गई। बैठक में निर्णय लिया कि भवनों निर्माण को लेकर वार्ड मेंबर से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। इसमें वार्ड सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का अतिक्रमण भवन मालिक के द्वारा तो नहीं किया गया है। नप अध्यक्ष अमरजोत बेदी ने बताया कि सफाई का

टेंडर इस हफ्ते लगाया जाएगा। इसके तहत ऊना शहर को चार भागों में बांटा गया है। इसके अलावा पांचवां टेंडर नालों को लेकर लगाया जाएगा।

शहर में पिज्ञापन को लेकर भी निविदा आमंत्रित की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले महीने टेंडर को लेकर स्टे ऑर्डर टूट गया था। पुरानी इमारत जैसे टीलू वाली हवेली को भी नगर परिषद इस हफ्ते गिराने का काम शुरू करेगी। यह हवेली किसी भी समय गिर सकती है और जान को नुकसान पहुंचा सकती है। कई जगहों पर पेवर्स लगाए जा रहे हैं।

इनकी गुणवत्ता जांचने के लिए नप ने इनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजने का निर्णय लिया है। नगर परिषद के हर वार्ड में दो से तीन लोहे के बेंच लगाए जाएंगे। नप लगभग 25 नए बेंचों की खरीद करेगी। वहीं नगर परिषद ने गोशाला के संचालन के लिए सरकार से राशि मांगने का प्रस्ताव रखा है। नप द्वारा संचालित गोशाला पर प्रतिमाह 6,00,000 का खर्च आ रहा है।

रैन बसेरा के लिए भेजा जाएगा रिमाइंडर

नप की आम बैठक में टीसीपी ऑफिस के समीप निर्मित रैन बसेरा की मरम्मत के लिए सरकार को रिमाइंडर भेजने का निर्णय लिया गया।

बीबीएन में जल्द मिलेगी हेलीपोर्ट की सुविधा, तीन करोड़ खर्च होंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन जल्द ही हेली टैक्सी सेवा से जुड़ेगा। यहां हेलीपोर्ट का तीन करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बीबीएन के बरोटीवाला में बने हेलीपैड वाले स्थल पर हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। यहां से दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला आदि के लिए हेली टैक्सी सेवाएं शुरू होंगी, जिससे लोगों सहित उद्योगपतियों को यहां आवागमन करने में सुविधा होगी, वहीं समय की भी बचत होगी।

उड़ान-2 के तहत बनने वाले इस हेलीपोर्ट के लिए करीब तीन करोड़ का टेंडर लगाया जा चुका है और औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद इसे अवार्ड करके कार्य जोरों पर शुरू होगा। उड़ान-2 के तहत हवाई सेवा देने वाले पवन हंस के उपाध्यक्ष ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन का दौरा करके बीते वर्ष बरोटीवाला में हेलीपेड बनाने की संभावनाएं तलाशी थीं।

बद्दी से शिमला की दूरी करीब 114 किलोमीटर है और छोटे वाहन में करीब 3:30 घंटे लग जाते हैं, जबकि बस में करीब 5 घंटे का सफर है। ऐसे में हेली टैक्सी शुरू होने से शिमला पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगेगा, जिससे लोगों के समय की बचत होगी। एडीबी के एक्सईएन सोमनाथ शर्मा ने कहा कि करीब तीन करोड़ रुपये का टेंडर लगा दिया गया है, जिसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। जिला पर्यटन अधिकारी विवेक चौहान ने कहा कि हेलीपोर्ट बनने से बीबीएन से हेली टैक्सी सेवाएं शुरू होंगी, जिसका क्षेत्र के लोगों सहित उद्योगपतियों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटकों की भी आमद बढ़ेगी।

पीने लायक नहीं कवाल खड्ड का पानी, एसीडीसीटी पाई गई छह

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

पच्छाद क्षेत्र की कवाल खड्ड में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलशक्ति विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं।

इस दौरान दोनों टीमों के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों टीमों ने रसायन युक्त पानी के सैंपल भरे। वहीं, खड्ड के आसपास स्थापित औद्योगिक इकाइयों की जांच भी की। टीम पता लगा रही है कि आखिर इस कवाल खड्ड में किस इकाई की रसायनयुक्त डस्ट आ रही है। इससे पहले जल शक्ति विभाग की टीम ने निरीक्षण में शुद्ध पेयजल के 20 मापदंडों में से एसीडीसीटी 6 पाई थी।

जबकि, एसीडीसीटी 6.4 से ऊपर होनी चाहिए। तभी पानी पीने योग्य हो सकता है। सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग पंकज चौधरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जूनियर पर्यावरणवादी नवीन कुमार के नेतृत्व में फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया और पानी के सैंपल भरे।

फिलहाल विभाग ने कवाल खड्ड से लाभान्वित होने वाली नारग-नोहरा व

डिलमन उठाऊ पेयजल योजना को दूसरे पेयजल स्रोत से जोड़ दिया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो खड्ड में रसायन युक्त पानी की एसीडीसीटी 6 पाई गई। इसके बाद विभाग लगातार ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर को मौके पर भेजकर पानी के उन सभी 20 मापदंडों की जांच में जुटा है।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

ट्रैफिक चेकिंग पर 500 से अधिक जेब में नहीं रख पाएंगे पुलिस कर्मी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एसपी बिलासपुर ने कड़े आदेश जारी किए हैं। एसपी दिवाकर शर्मा ने कहा है कि ट्रैफिक चेकिंग पर जाने वाले पुलिस कर्मी अपनी जेब में 500 रुपये से अधिक नकद राशि नहीं रखेंगे। अधिक पैसे साथ रखने पर इसका पूरा उल्लेख रोजनामचा में करना होगा। ऐसा न करने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि कि भ्रष्टाचार करने वाले और उसमें संलिप्त कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। आदेश के अनुसार पुलिस नाका, ट्रैफिक जांच, नाके पर जाने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देनी होगी। आदेशों की पालना न करने वाला मुलाजिम भ्रष्ट आचरण में संलिप्त माना जाएगा। यातायात चेकिंग और नाकों के दौरान कोई भ्रष्टाचार न हो इसके लिए यह कदम उठाया गया है।

फोरलेन में खनन कर रही कंपनी का काम रोका, मांगा रिकॉर्ड

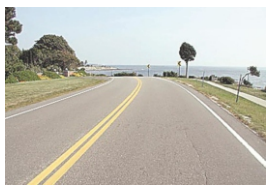

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गरामोड़ा से कैंची मोड़ पर खनन कर रही कंपनी पर संबंधित विभाग ने शिकंजा कस दिया है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर काम को रोक दिया है। कंपनी के अधिकारियों को माइनिंग की मंजूरी के दस्तावेज मुहैया करवाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त दस्तावेज माइनिंग विभाग के शिमला कार्यालय में देने होंगे। इसके बाद ही कार्य शुरू हो पाएगा। पुलिस आने वाले दिनों में भी मौके पर निगरानी रखेगी। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने इस संबंध में शिकायत की थी। कहा था कि खनन कर पूरा पत्थर और अन्य सामग्री साथ लगते राज्य पंजाब में डंप कर बेची जा रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपये का चूना लग रहा है। शिकायत में कहा है कि पहले भी इस प्रकार से अवैध माइनिंग कर सामग्री पंजाब पहुंचाई जा चुकी है। समिति ने खनन अधिकारी से मांग की है कि पंजाब में जो डंप की गई सामग्री है, उसका भी पूरा डाटा मुहैया करवाया जाए। कंपनी से नुकसान की वसूली की जाए। इस पर खनन अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन समिति को दिया है। उधर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि खनन कर रही कंपनी का काम रोका गया है। जब तक कंपनी दस्तावेज मुहैया नहीं करवाती, तब तक काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है।

विस्तारीकरण का विरोध, गगल हवाई अड्डे के गेट पर सात पंचायतों का धरना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के विरोध में हाल ही में सात पंचायतों गगल, नंदेहड़, सहौड़ा, इच्छी, मटौर, रिछयालू, सनौरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के गेट पर धरना दिया। ग्रामीणों ने एयरपोर्ट विस्तार पर रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि सरकार को भूमि अधिग्रहण से पहले हजारों किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, बेरोजगारों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। गठित संघर्ष समिति के बैनर तले गुस्साए ग्रामीणों ने पुराना मटौर से गगल एयरपोर्ट तक रोष रैली निकाली थी। कांगड़ा ब्लॉक प्रधान यूनियन के अध्यक्ष एवं सहौड़ा पंचायत के प्रधान विजय कुमार विजू ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से जहां सैकड़ों परिवार उजड़ जाएंगे, वहीं कूहलें बंद होने से उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों विजय शर्मा, कुलभाष, विजय कुमारू, रविंद्र बाबा, प्रदीप, वेद चौधरी, बिंदु धनोटिया, इकबाल, हंसराज, वेद चटानी, बलदेव, कुलभूषण, अशोक कुमार, जसबीर, सुनीता देवी, रोशन लाल शामिल थे। लोगों ने कहा कि गांवों के उजड़ने से कई लोग बेरोजगार होंगे। सरकार रोजगार देने में तो असमर्थ है, लेकिन जो स्वरोजगार से परिवार पाल रहे हैं, उन्हें भी उजाड़ा जा रहा है।

नासा पहुंचने से एक कदम दूर कांगड़ा के अर्णव शर्मा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा के गांव नलेटी का अर्णव शर्मा नासा में पहुंचने से एक कदम की दूरी पर है। अर्णव डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने देशभर के टॉप-60 प्रतिभागियों में स्थान बनाया है। इसमें हिमाचल के मात्र 2 छात्र हैं।
अब मुंबई में 18 मार्च से सेमीफाइनल शुरू होंगे। इसमें ही नासा जाने का टिकट भी तय होगा। इस दौरान नासा भ्रमण के लिए चयनित छात्र विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के बारे में भी जान सकेंगे, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। स्कूल सुपर लीग के अंतिम चरण में सेक्रेड हर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिधपुर (धर्मशाला) में पढ़ाई कर रहे नलेटी के अर्णव शर्मा हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग सीजन-2 में इस साल लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अंतिम चरण के लिए सिर्फ 60 विद्यार्थियों को ही मुंबई बुलाया गया है। अर्णव शर्मा को टीम के कैप्टन के रूप में शिरकत करने का अवसर मिलेगा।

भारत-दक्षिण अफ्रीका वन-डे के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरु

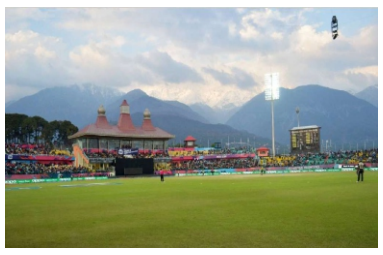

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकदिवसीय क्रिकेट मैच के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। सबसे सस्ता टिकट 850 रुपये में क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा। दस हजार रुपये की सबसे महंगा टिकट कॉरपोरेट बॉक्स का है। 850 रुपये में क्रिकेटप्रेमी ईस्ट स्टैंड-एक और तीन से मैच देख सकते हैं। 1200 रुपये में नॉर्थ वेस्ट स्टैंड के नॉर्थ-एक, नॉर्थ-दो, नॉर्थ-एक लेवल-एक, नॉर्थ-दो के लेवल-एक से मैच देखा जा सकता है।
1250 रुपये में क्रिकेट प्रेमी ईस्ट स्टैंड-दो और वेस्ट स्टैंड-दो से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। 1800 रुपये के टिकट में ईस्ट स्टैंड-तीन और वेस्ट स्टैंड-एक से मैच देख सकते हैं। पवेलियन टैरेस से मैच देखने के लिए दर्शकों को 2500 रुपये का टिकट खरीदना होगा। 3500 रुपये में नॉर्थ वीआईपी स्टैंड और 10 हजार रुपये में कॉरपोरेट बॉक्स से क्रिकेट प्रेमी मैच का आनंद ले सकते हैं।

सभा के 800 ऑपरेटरों को मिलेगा 15-15 लाख का दुघर्टना बीमा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं परिवहन सहकारी सभा खारसी ने अपने ट्रक ऑपरेटरों को ग्रुप इश्योरेंस की सुविधा दी है। सभा के प्रति ऑपरेटर 15 लाख का दुर्घटना बीमा करवाया है। वर्तमान में सभा के अधीन 800 से अधिक ऑपरेटरों की गाड़ियां चल रही हैं। सभा के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह योजना एसबीआई के साथ मिल कर चलाई गई है। प्रदेश में किसी भी ट्रक यूनियन की ओर से इस प्रकार की सुविधा पहली बार ऑपरेटरों को दी जा रही है। उन्होंने कहा अगर किसी भी ऑपरेटर की हादसे के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 15 लाख की वित्तीय सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सड़क हादसे या किसी अन्य हादसे में अपंग होने पर अपंगता की प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रक ऑपरेटर हादसे के बाद अस्थायी अपंगता के कारण अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 104 सप्ताह तक 10 हजार रुपये प्रति सप्ताह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अगर हादसे में किसी व्यक्ति का एक अंग या इससे अधिक कट जाता है या आंखों की रोशनी हादसे में चली जाए तो उस सुरत में भी 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के लाभ देने के लिए सभा हर ऑपरेटर के 832 एसबीआई को अदा करेगी।

पालमपुर में ऑनलाइन भरे जाएंगे नप के सभी बिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
नगर परिषद पालमपुर के दायरे में आने वाले लोग अब अपने पानी, गृह और दुकानों का किराया आदि ऑनलाइन से भर सकते हैं। नगर परिषद पालमपुर की अध्यक्ष राधा सूद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें नप पालमपुर ने कई फैसले लिए। नप की बैठक में सबसे बड़ा यह फैसला लिया गया कि लोग अब आने वाले दिनों में घर बैठे ही नगर परिषद के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इनमें घर, दुकान, पानी आदि सभी तरह के बिल होंगे, जबकि लोग नप आकर स्वाइप मशीन या कैश से भी अपने बिल भर सकते हैं।
लोगों को इसके लिए हर सुविधा होगी। यह काम जल्द शुरू हो जाएगा। नप ने फैसला लिया कि सीता राम पार्क और नेहरु चौक के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। साथ ही शहर में बनी पुस्तकालय की ओर मंजिल बनाई जाएगी। इस मंजिल में समाज सेवी डॉ. राम अपनी माता की याद में अपना योगदान देंगे। नप की अध्यक्ष राधा सूद ने कहा कि आने वाले दिनों में नप के दायरे में आने वाले लोग अपने नप को देने वाले सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे उन्हें घर बैठे ही यह सुविधा मिल जाएगी।

कांगड़ा में मकानों का सूचीकरण कार्य 16 मई से होगा शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
जनगणना-2021 के तहत कांगड़ा जिला में घरों का सूचीकरण और जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य 16 मई से लेकर 30 जून तक किया जाएगा। इसके लिए जनगणना अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
दूसरे चरण में हिमच्छादित क्षेत्रों में 11 से 30 सितंबर तक जनगणना का कार्य किया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में नौ से लेकर 28 फरवरी 2021 तक जनगणना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने डीआरडीए सभागार में जनगणना अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बतौर मुख्यातिथि दी। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना देश के विकास का आधार है।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों की सफलता के लिए जनगणना के सही आंकड़ों का होना आवश्यक है।
यह तभी संभव है, जब जनगणना कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों और अपने कार्य को समर्पण एवं निष्ठा के साथ-साथ समय पर पूरा करें। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और स्थानीय निर्वाचन में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर ही नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए मूल्यवान सूचना प्राप्त होती है।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनगणना कार्य से संबंधित समस्त पहलुओं को सूक्ष्मता से समझें, ताकि जनगणना के कार्य को त्रुटि रहित एवं समयबद्ध पूर्ण किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारी शंकाओं का निवारण करें।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को दस साल का अनुभव जरुरी, बोर्ड ने मांगे आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वही शिक्षक कर सकेंगे। जिनके पास चार से लेकर 10 वर्ष तक का अनुभव होगा।
स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए विभिन्न अध्यापकों ने आवेदन मांगे हैं। इसके लिए सात कॉलम का एक परफोरमा भरकर बोर्ड कार्यालय को भेजना होगा। इसके लिए इच्छुक अध्यापक 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने बताया कि बोर्ड की ओर से संचालित की जाने वाली मैट्रिक और जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्थल मूल्यांकन प्रणाली से करवाना जाना है।
इसके लिए मुख्य परीक्षक और उपनिरीक्षकों को मूल्यांकन के लिए बोर्ड की ओर से नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड के नियम के अनुसार मुख्य परीक्षक के लिए कम से कम 10 वर्ष और उप परीक्षक के लिए कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात अध्यापक और प्राध्यापक 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

साइंस लैब में अटेंडेंट और सहायक की नियुक्तियां की जाएं : संघ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर
राजकीय वरिष्ठ बाल माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में विज्ञान अध्यापक संघ की बैठक प्रधान दिनेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें काफी संख्या में विज्ञान अध्यापकों ने भाग लिया तथा गत दिवस सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत एक सरकारी स्कूल में साइंस प्रैक्टिकल मैट्रिक परीक्षा के दौरान तीन छात्राओं पर तेजाब फेंकने की घटना पर चिंता जताई गई। संघ ने सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हाई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षा के दौरान लैब अटेंडेंट या अन्य सहायक नियुक्त करवाए जाएं।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य को भी निर्देश दिए जाएं कि साइंस प्रैक्टिकल मैट्रिक परीक्षा के दौरान होने वाली परीक्षा में लैब अटेंडेंट का होना अति आवश्यक किया जाए। जिन-जिन हाई स्कूलों में लैब अटेंडेंट के पद रिक्त हैं, उनको अति शीघ्र भरा जाए। बैठक में साइंस अध्यापक संघ ब्लॉक प्रधान रजिंद्र कुमार, जिला महासचिव करुण राणा, वित्त सचिव रविंद्र सिंह, सुजानपुर ब्लॉक प्रधान नरेश कुमार, बिझड़ी ब्लाक प्रधान कमल चौहान, भोरंज ब्लॉक पवन शर्मा, शिवानी, पूर्णिमा, सीमा शामा, रीना कुमारी, मधुबाला आदि उपस्थित रहे।

अनुमति 98 की, कुल्हाड़ी चला दी 195 पेड़ों पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर
पेड़ कटान का लाइसेंस लेकर हमीरपुर जिले में वन विभाग की आंखों में धूल झोंक अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। उपमंडल भोरंज के सधरियाण में निजी भूमि पर बिना अनुमति के खैर के 195 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। जबकि, ठेकेदार ने वन विभाग से खैर के 98 पेड़ों को काटने की अनुमति ले रखी थी। गुप्त सूचना के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो हमीरपुर की टीम ने मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश की। विजिलेंस ब्यूरो ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि संबंधित ठेकेदार ने वन विभाग से 98 पेड़ों को काटने की अनुमति ले रखी थी लेकिन, मौके पर 195 पेड़ कटे हुए मिले। सौ से अधिक खैर के पेड़ों के ठूंठ जड़ों समेत उखाड़ कर छिपा दिए गए। विजिलेंस की यह कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। विजिलेंस ने काटे गए खैर के पेड़ों की सारी लकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।

जिले में लगेंगे 80 नए उद्योग, सवा चार करोड़ रुपये का होगा निवेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर
उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की एक बैठक हुई। बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 46 आवेदन रखे गए थे। जिनमें 14 जिला उद्योग विभाग, 3 खादी बोर्ड एवं 29 खादी ग्रामोद्योग आयोग से समिति के समक्ष रखे गए थे। जिला स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 45 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 36 आवेदन रखे गए थे, जिनमें समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 35 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। इन सभी उद्योगों में लगभग 4.25 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित है एवं लगभग 450 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिन्हें आगामी कार्यवाही के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। उपायुक्त ने जिला के बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

चंबा मेडिकल कॉलेज में जल्द ज्वाइन करेंगे पांच नए डॉक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए पांच डॉक्टरों को ज्वाइनिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेशों के बाद दो डॉक्टरों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तीन अन्य डॉक्टर भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज चंबा में ज्वाइन कर सकते हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है।

इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को डॉक्टरों के साक्षात्कार लेने के निर्देश दिए हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरी ने बताया कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए पिछले दिनों देहरादून, पठानकोट, जम्मू - कश्मीर और चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों में साक्षात्कार लिए गए। इसके बाद पांच डॉक्टरों का चयन हुआ। इन डक्टरों की लिस्ट प्रदेश सरकार को भेजी गई। सरकार ने डॉक्टरों चंबा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में जिन पांच डॉक्टरों के ज्वाइनिंग के ऑर्डर हुए हैं। इसमें एक हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर हैं। जबकि चार एमबीबीएस (जूनियर रेजिडेंट) डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों के आने से चंबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एक जूनियर रेजिडेंट की महिला रोग ओपीडी सेवाएं लेने की योजना बना रहा है। मेडिकल कॉलेज में एक महिला विशेषज्ञ होने से आए दिन गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सरकार से महिला रोग विशेषज्ञ की मांग की है। जोकि जल्द ही पूरी हो होने की उम्मीद हैं। मेडिकल कॉलेज में पूरी की जा रही है।

कुल्लू अस्पताल के निरीक्षण को पहुंची टीम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को जांचने के लिए तीन सदस्यीय टीम पहुंच गई है। टीम ने भी अस्पताल में कई गतिविधियों का निरीक्षण किया है। कायाकल्प के लिए तैयार किए गए मानकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके तहत कायाकल्प खिताब दिया जाता है।

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को 2018 को भी कायाकल्प का खिताब मिल चुका है और इस साल भी कुल्लू अस्पताल इस इनाम की दौड़ में शामिल है। डॉ. मेहताब सिंह, डॉ. अशोक गुप्ता तथा डॉ. अरविंद धीमान की टीम ने चार जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का निरीक्षण किया। इसमें अस्पताल के साफ-सफाई, सुविधाएं, कैंटीन आदि अन्य गतिविधियों को देखा है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील चंद्र शर्मा ने कहा कि कायाकल्प की तीन सदस्यीय टीम कुल्लू पहुंची और चार मार्च तक टीम तय मानकों के अनुरूप कुल्लू अस्पताल का निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि 2018 में कुल्लू अस्पताल को बेहतर सुविधा के लिए कायाकल्प का इनाम मिल चुका है।

एसडीएम शहर में अतिक्रमणकारियों पर की कार्रवाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

एसडीएम चंबा पुलिस और नगर परिषद की टीम को लेकर शहर में अतिक्रमण करने वाले दो दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे। इसके साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी कि वे दोबारा दुकानों का सामान सड़क पर न रखें।

दोबारा सड़क पर सामान नजर आने पर उनका सामान जब्त किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों को अतिक्रमण करने से परहेज करना होगा। बीते दिनों एसडीएम की अगुवाई में नगर परिषद और पुलिस की टीम ने पूरे बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान ज्यादातर दुकानदार ऐसे पाए गए, जिन्होंने दुकानों का सामान सड़क पर सजा रखा था। इसकी वजह से राहगीरों सहित वाहन चालकों को सड़क पर आवाजाही करने में परेशानी हो रही थी। जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहले कई बार आगाह किया जा चुका है। मगर दुकानदार हर बार प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा कर रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर दो दर्जन से अधिक दुकानदारों के काटे गए चालान को प्रशासन कोर्ट में पेश करेगा। यहां पर दुकानदारों को नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ एसडीएम ने शहर में बिना परमिट से सजी रेहड़ी-फड़ी को भी हटाया। इसके साथ ही नप को निर्देश दिए कि बाजार में बिना अनुमति रेहड़ी फड़ी न लगाएं। पुलिस को इसको लेकर नियमित जांच करने के निर्देश एसडीएम ने दिए हैं। एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार ऑन कॉल फ्लाइंग स्कवायड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अगर किसी स्कूल में नकल हो रही हो तो इसकी सूचना विभाग के कार्यालय नंबर पर भी दी सकती है। सूचना के बाद ऑन कॉल फ्लाइंग स्कवायड स्कूल में दबिश देगा। कार्यालय के दूरभाष नंबर 01899–222211 पर शिकायत की जा सकती है। हालांकि, विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया जाना था। लेकिन ऐसा इस बार की परीक्षाओं में संभव नहीं हो सका है। बोर्ड परीक्षा के दौरान एसडीएम लेवल की एक कमेटी बनेगी। जबकि इंस्पेक्शन विंग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की टीम भी शामिल होगी। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी स्थापित किए हैं तो स्कूल प्रमुखों को सीसीटीवी का बैकअप रखने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग चंबा के उपनिदेशक देवेंद्र पॉल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए जहां फ्लाइंग स्क्वायड गठित किए जा रहे हैं वही, पहली बार ऑन कॉल फ्लाइंग स्कवायड का भी प्रावधान किया गया है। विभाग के कार्यालय नंबर 01899–222211 पर लोग नकल की सूचना दे सकते हैं।

मेडिकल कॉलेज नेरचौक में न्यूरो ओपीडी, जल्द शुरु होगी सर्जरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नर्वस सिस्टम (न्यूरो) की समस्या से जूझ रहे रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़, शिमला या टांडा नहीं जाना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भी अब इलाज संभव होगा। न्यूरो विभाग में पिछले 29 साल से आईजीएमसी में बतौर न्यूरो सर्जन सेवाएं देने वाले चिकित्सक डॉ. आरसी ठाकुर ने बीते दिनों नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार से एक्सटेंशन मिली है। अब वह नेरचौक मेडिकल कॉलेज में न्यूरो विभाग में अपनी सेवाएं देंगे और यहां न्यूरो से संबंधित इलाज की बेहतर अधोसरंचना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रजनीश पठानिया ने डॉ. आरसी ठाकुर के न्यूरो विभाग में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही न्यूरो की ओपीडी शुरू होगी। सर्जरी शुरू करने के भी प्रयास होंगे। वर्तमान में न्यूरो की ओपीडी नहीं लगती है। मंडी जिले में इस रोग का इलाज न होने से लोगों को चंडीगढ़, शिमला या टांडा जाना पड़ता है। डॉ. रूपचंद ठाकुर ने बताया कि 1992 में वह पीजीआई से आए और उन्होंने आईजीएमसी ज्वाइन किया था। 29 साल तक आईजीएमसी में अपनी सेवाएं दीं। सरकार ने अब एक्सटेंशन दी है तथा प्रोफेसर ऑफ सर्जरी लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है। कोशिश रहेगी कि न्यूरो सर्जरी के मामलों को भी देखेंगे। अभी न्यूरो सर्जरी में यहां ज्यादा कुछ है नहीं, सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। जैसे-जैसे यहां पर मशीनरी आएगी, न्यूरो सर्जरी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। न्यूरो सर्जरी ब्रेन पेन से संबंधित है तथा इस तरह की बीमारियों के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में इस तरह की सुविधाएं आम जनमानस को मिलें।

चंबा मेडिकल कॉलेज में पहुंची एमसीआई टीम, विभिन्न विभागों में दी दबिश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमसीआई की टीम ने बीते दिनों औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण पर पहुंची तीन सदस्यीय एमसीआई टीम ने मेडिकल कॉलेज के सभी वार्डों का जायजा लिया। इसके अलावा आपातकालीन कक्ष की व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को भी जांचा। वार्ड में भर्ती मरीजों से भी एमसीआई टीम ने सवाल जवाब किए। इसके अलावा एमसीआई ने टीबी अस्पताल सहित अखंड खंडी पैलेस में निरीक्षण किया। एमसीआई टीम बीते दिनों चंबा में रहेगी और मेडिकल कॉलेज के अन्य विभागों में व्यवस्थाओं की जांच परख करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमसीआई की तीन सदस्यीय टीम ने पहले इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्था जांची। इसके बाद चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में समस्त रिकॉर्ड खंगाला। इस दौरान नजर आई खामियों को दुरूस्त करने के आदेश दिए। विभिन्न विभागों में भी टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया। जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई। गौरतलब है कि इससे पहले एमसीआई की टीम ने अक्तूबर माह में मेडिकल कॉलेज चंबा का दौरा किया था। इस दौरान कुछेक आपत्तियां लगाई थी। जिसे दुरूस्त करने के लिए कहा गया था। इन आपत्तियों की प्रगति रिपोर्ट बीते दिनों एमसीआई टीम ने जांची। फिलहाल एमसीआई मेडिकल कॉलेज चंबा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार करती है। इसका पता निरीक्षण के बाद ही पता चल पाएगा। एमसीआई के दौरे को लेकर बीते दिनों अस्पताल चकाचक दिखी।निरीक्षण से पहले मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश गुलेरी ने बताया कि एमसीआई टीम ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है।

जिले की 10 चौकियों में भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

आम जनता को न्याय प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से मंडी जिले की दस पुलिस चौकियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमोदित किया है। अब चौकियों में एफआईआर दर्ज हो सकेगी। पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस में शिकायत करवाने के बाद अब शिकायतकर्ता को एफआईआर की प्रति उसी समय पुलिस चौकी में दे दी जाएगी। इसमें उनकी शिकायत दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम दर्ज होगा। उसका संपर्क नंबर भी संबंधित चौकी में मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए शिकायतकर्ता को संबंधित क्षेत्र के थाना में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए मंडी जिले की दस पुलिस चौकियों में यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अनुमोदित पुलिस चौकी एवं क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना सुंदरनगर के लिए अनुमोदित चौकी सलापड़, निहरी के लिए पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर, पांगणा पुलिस चौकी के लिए थाना करसोग, रिवालसर पुलिस चौकी के लिए थाना बल्ह, पंडोह और कोटली पुलिस थाना सदर, कमांद पुलिस थाना पधर, बस्सी पुलिस थाना जोगिंद्रनगर, संधोल एवं टिहरा संबंधित पुलिस थाना धर्मपुर में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

छेश्चू मेले के शुभारंभ को नहीं पहुंचे कृषि मंत्री, एसडीएम ने किया शुभारंभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल रिवालसर में बीते दिनों को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय छेश्चू मेले का फीका शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने करना था लेकिन वह विधानसभा सत्र होने के चलते नहीं पहुंच पाए।

मेले का शुभारंभ बल्ह के कार्यकारी उपमंडलाधिकारी राजेंद्र ठाकुर ने किया। कोरोना वायरस के भय के कारण इस बार पांच देशों के बौद्ध अनुयायी रिवालसर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे यहां रौनक गायब हैं। मेले के शुभारंभ पर स्थानीय स्कूली बच्चों और महिला मंडलों, ईश्वरीय विश्वविद्यालय साधना केंद्र की ओर से देश भक्ति गीत और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। त्रिभुवन महिला मंडल पटड़ीघाट की महिलाओं ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर लघु नाटिका पेश की।

तहसीलदार रिवालसर जैमल चंद, नायब तहसीलदार रमेश चौहान, स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष लाभ सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मीना गुप्ता, लीला वशिष्ठ, रोजी सोनी, मनोनीत पार्षद यशपाल ठाकुर, राज कमल, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।

जातिगत आरक्षण, एससीएसटी एक्ट रद्द करे सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

सामान्य वर्ग कल्याण समिति ने देश में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है। समिति का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था के कारण देश में सामान्य वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। कहा कि देश में जातिगत आरक्षण व्यवस्था के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा, वहीं देश के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता समिति के संयोजक और हिमाचल प्रदेश राजपूत सभा के महासचिव केएस जंवाल ने की। इस मौके पर राजपूत सभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में आजादी से पहले राजाओं से लेकर प्रजा तक सभी वर्गों ने वर्ण व्यवस्था के तहत कार्य किया। अपने-अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन किया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए और कुछ जातियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। 70 साल बीत जाने के बाद भी इसे अब हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को बंद करने और एससीएसटी एक्ट को रद्द करने की मांग उठाई। केएस जम्बाल ने कहा कि सामान्य वर्ग की ज्वलंत समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने तथा राज्य एवं केंद्र सरकार से इनका न्यायोचित हल करवाने के लिए संघर्ष जारी है। इस मौके पर राजपूत सभा से सुरेंद्र सेन, राजा ठाकुर, महाजन सभा के प्रधान एमएल गुप्ता, राजपूत कल्याण ट्रस्ट कांगड़ा के चेयरमैन कुलदीप ठाकुर, राजपूत महासभा के अध्यक्ष टेक चंद राणा, नामधारी सभा के प्रधान हरमीक सिंह, खत्री सभा के प्रधान पीसी विष्ट, आहलूवालिया सभा के प्रदेशाध्यक्ष रमेश वालिया, क्षत्रिय सभा के प्रधान भूपेंद्र सेन, राजपूत सभा सुंदरनगर के प्रधान राजेंद्र भंडारी सहित अन्य मौजूद रहे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

गठिया रोग

अगर आपके घुटनों, कूल्हों, हाथ व शरीर के अन्य किसी जोड़ पर दर्द होता है, तो समझ लीजीये कि आपको गठिया की परेशानी है। गठिया की बीमारी से परेशान लोगों को इतना भयानक दर्द होता है, कि वे बैचैन हो जाते है। दर्द का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, और फिर ये धीरे धीरे गठिया का रोग बन जाता है। आज के समय में ये बहुत आम बीमारी है, जो किसी भी प्रकार से हो सकती है। साधारण शब्दों में कहा जाये तो अगर आपके एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द व् सुजन रहती है तो आप गठिया रोग से पीड़ित है।

गठिया के लक्षण

दर्द के साथ साथ कुछ और लक्षण होते है, जैसे सुजन,
जोड़ो के आस पास लाल होना,
शरीर के उस हिस्से को हिलाने में तकलीफ होना,

जकड़न

गठिया में तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि ये शरीर के जोड़ो को छुने से भी दर्द का अहसास होता है। गठिया का रोग मुख्यतः 100 से ज्यादा प्रकार का होता है। गठिया

हलके से गंभीर स्तिथि में अलग होता है।

गठिया का कारण

गठिया शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ जाने से भी होता है। यह वह विषेला पदार्थ है जिसे शरीर, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को करने में किडनी मुख्य भूमिका निभाती है। जब किडनी अपना काम सुचारू रूप से नहीं करती है, तब ये पदार्थ शरीर में ही इक्कठा होने लगता है। और फिर ये जोड़ो में जाकर दर्द का कारण बनता है।

यह रोग अनुवांशिक भी होता है, मतलब परिवार के एक सदस्य से दुसरे में जाता है।

गठिया रोग में क्या सावधानियां बरतें

1. अगर आपके जोड़ों में जरा सा भी दर्द, शरीर में हल्की अकड़न है तो भी सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं।
2. कोशिश करें कि दिनचर्या नियमित रहे।
3. डॉक्टर की सलाह पर नियमित व्यायाम करें।
4. नियमित टहलें, घूमें-फिरें, व्यायाम एवं मालिश करें।
5. सीढ़ियां चढ़ते समय, घूमने-फिरने जाते समय छड़ी का प्रयोग करें।
6. ठंडी हवा, नमी वाले स्थान व ठंडे पानी के संपर्क में न रहें।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

विश्व के वन भीषण अग्निकांड पर्यावरण के लिए एक चेतावनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो, पर्यावरण हमारा सरंक्षण करेगा। यदि समय रहते हमने इसका संरक्षण नहीं किया तो धरती पर मानव व अन्य जीव-जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं होगा। किसी भी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहां की जैव विविधता से आँकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों को बेरहमी से उजाड़ा गया हैं, लेकिन हमारी वन संपदा दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्त्रोत वृक्ष है इसलिए वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है । यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव जंतुओं का धरती पर अस्तित्व नहीं होगा । हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। वर्ष 1987 में रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई । भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट वार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आरोपण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 प्रतिशत है । वन क्षेत्रफल में वृद्धि 3976 वर्ग किलोमीटर हुई है जो 0.56 प्रतिशत है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल , मेघालय ,मणिपुर, नागालैंड है । क्षेत्रफल में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के आवरण में 334 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश ने देश के अग्रणी राज्यों में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हरित आवरण में यह वृद्धि प्रदेश में चलाए जा रहे वन संरक्षण व पौधारोपण के लिए सतत प्रयासों से संभव हुई है, वन क्षेत्र बढ़ने के संकेत सुखद है लेकिन पर्यावरण सहेजने के लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे। बेशक भारत व हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग का असर भारत पर नजर आने लगा है। अमेजन की जंगल विश्व के

सबसे बड़े रेनफॉरेस्ट माने जाते है। इन वनों से विश्व 20 से 25 प्रतिशत ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसलिए यह भीषण अग्निकांड पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। वर्ष 2015 में इंडोनेशिया में 26 लाख हेक्टेयर में आग लगी थी। लेकिन वर्ष 2019 में इंडोनेशिया की बोर्नियो में वर्षा वनों में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया इस दौरान आग के कारण 70 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कनाडा में 1 वर्ष में उत्सर्जित होती है। ऑस्ट्रेलिया जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया में आग से मखमली कीड़ों जैसी कई प्रजातियां खत्म होने की आशंका है। कीड़ों का आकार भले ही छोटा हो लेकिन पूरा ब्रह्मांड उनके कंधों पर होता है। वह हमारे परिवेश को साफ रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे आसपास कूड़े का ढेर नहीं लगने देते क्योंकि उसे मुफ्त में साफ करते हैं । उनके रहने की जगह की रक्षा की जाए तो वे सुरक्षित रहते है । जली हुई दीवारें और आग से भागते हुए शरणार्थियों की, समुद्र तटों पर उमड़ी भीड़ इस भयानक आग को बताने के लिए काफी है। इसलिए दुनिया भर की सरकारों को इस त्रासदी से सबक सीखते हुए तत्काल पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए। पर्यावरणविदों की चेतावनी को नजरअंदाज करना और महंगा पड़ सकता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लगी यह भीषण आग सभी देशों के लिए एक सबक है भारत के विभिन्न प्रांतों और हिमाचल प्रदेश में भी इस समय तुरंत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में इन गलतियों को दोहरहा कर विनाश लीला देखने, वह सहने को हम मजबूर ना हो । भविष्य में भीषण आग के मंजर को महसूस किए बिना खेतों में आग लगाना, शिकारियों व अन्य लोगों का बिना सकारात्मक उद्देश्य जंगलों में प्रवेश वर्जित होना चाहिए । बिना सोचे समझे खेतों को साफ करने के लिए आग लगा देना व उसके दुष्परिणामों के बारे में किसानों व बागवानों को समय-समय पर जागरूक किया जाना चाहिए। जंगल के साथ रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क व जागरूक रहने की आवश्यकता है। वन संरक्षण कमेटियां गठित करके उन पर यह उत्तर दायित्व सौंपकर वनों का सरंक्षण किया जाना चाहिए । वन विभाग के द्वारा तारबंदी व सक्षम संचार व्यवस्था व आपदा प्रबंधन के तहत प्रशिक्षण आवश्यक है। भारत व हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं उन्हें स्कूल में विशेष रूप से जंगलों में लगने वाली आग के दुष्परिणामों बारे विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है, ताकि हम अपने वनों को बचा सकें व पर्यावरण सरंक्षण का हमारा सपना साकार हो सके।

अजय विशिष्ट, सदस्य राज्य
सलाहकार समिति, एनएसएस शिक्षा
निदेशालय हिमाचल प्रदेश
कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस राजकीय
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
संजौली शिमला -6, हिमाचल प्रदेश

लेखक के ये निजी विचार हैं जिसके लिए लेखक की पूर्ण जिम्मेवारी रहेगी ।

कानून की नजर में देशद्रोह

क्या है देशद्रोह

भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124 में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार - विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है ।

कहां से आया नियम

देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था । इसे 1860 में बनाया गया और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया ।

इन पर हुआ है लागू

1. 1870 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ वीकली जनरल में 'यंग इंडिया' नाम से आर्टिकल लिखे जाने की वजह से किया था । यह लेख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया था ।

2. बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर 1962 में राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले में देशद्रोह के मामले में केस दर्ज किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी । केदारनाथ सिंह के केस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक बेंच ने भी आदेश दिया था । इस आदेश में कहा गया था, 'देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है, जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े ।

3. 2010 को बिनायक सेन पर नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर इस केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । बिनायक के अलावा नारायण सान्याल और कोलकाता के बिजनेसमैन पीयूष गुहा को भी देशद्रोह का दोषी पाया गया था । इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन बिनायक सेन को 16 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई थी ।

4. 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को उनकी साइट पर संविधान से जुड़ी भद्दी और गंदी तस्वीरें पोस्ट करने की वजह से इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया । यह कार्टून उन्होंने मुंबई में 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए एक आंदोलन के समय बनाए थे ।

5. 2012 में तमिलनाडु सरकार ने

कुडनकुलम परमाणु प्लांट का विरोध करने वाले 7 हजार ग्रामीणों पर देशद्रोह की धाराएं लगाईं थी ।

6. 2015 में हार्दिक पटेल कन्हैया कुमार से पहले गुजरात में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल को गुजरात पुलिस की ओर से देशद्रोह के

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी: 94180 25649
आभिलाषा 'आकड़ा' से सहयोग साभार

8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस?

- सालों से दुनियाभर के लोग आज के दिन महिला दिवस मनाते आ रहे हैं लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ?

कब शुरु हुआ महिला दिवस?

दरअसल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था जब 15 हजार औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमरीका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। इसके अलावा इतिहास के अनुसार समानाधिकार की यह लड़ाई आम महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी। प्राचीन ग्रीस में लीसिसट्राटा नाम की एक महिला ने फ्रेंच क्रांति के दौरान युद्ध समाप्ति की माँग रखते हुए इस आन्दोलन की शुरूआत की, फारसी महिलाओं के एक समूह ने वरसेल्स में इस दिन एक मोर्चा निकाला, इस मोर्चे का उद्देश्य युद्ध की वजह से महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकना था। सन 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा पहली बार पूरे अमेरिका में 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया गया। सन 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा कोपनहेगन में महिला दिवस की स्थापना हुई।

1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटजरलैंड में लाखों महिलाओं द्वारा रैली निकाली गई। मताधिकार, सरकारी कार्यकारिणी में जगह, नौकरी में भेदभाव को खत्म करने जैसी कई मुद्दों की माँग इस रैली में की गई। 1913–14 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, रूसी महिलाओं द्वारा पहली बार शांति की स्थापना के लिए फरवरी माह के अंतिम रविवार को महिला दिवस मनाया गया। यूरोप भर में भी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 1917 तक विश्व युद्ध में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, रूसी महिलाओं ने फिर रोटी और शांति के लिए इस दिन हड़ताल की। हालांकि राजनेता इसके खिलाफ थे, फिर भी महिलाओं ने एक नहीं सुनी और अपना आन्दोलन जारी रखा और फलतः रूस के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और सरकार को महिलाओं को वोट देने के अधिकार की घोषणा करनी पड़ी। महिला

दिवस अब लगभग सभी विकसित, विकासशील देशों में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए।

Shimla Smart City with a 'Non-Smart' Framework

With a noble thought to transform the slum-like conditions of our Indian cities and modernise them, there is an opportunity for a holistic envisioning of the ideal city and channelising the actions accordingly. This is an exceptional opportunity in terms of the resources as well as the schematic mandate for all those cities which are covered under the Smart City Scheme, and more depends on the capabilities and smartness of people responsible for its implementation.

As the raindrops fall without any biasness or prioritisation on different elements of the earth, the benefit to different strata of the land and all life forms always varies. More the capacity to absorb the water, more the scope of productivity of the land. Similarly, the Smart City initiative by the Government provides for the equal provisions to all the benefactors, but it depends on the effectiveness of the machinery going to make use of such offerings of the scheme. Furthermore, the efficacy of the machinery depends upon the fundamental parameters, viz –

a) Composition of the machinery in terms of expertise

b) Capability of the machinery to think out of the box to envision the likely Smart City

c) Level of seriousness at the administrative and political levels

d) Level of community involvement in participatory planning

e) Ascertaining timeline for each action with accountability.

When the above-listed parameters are applied in the process of transforming Shimla into a Smart City, the aspect of effectiveness seems getting diluted for the following reasons –

a) The responsibility of the Smart City lies with a separate legal entity, named Shimla Smart City Limited, where the Board comprises of the bureaucrats in the majority. There is no renowned town planner having exposure or prior experience of developing a city. Today we a look forward to visiting Chandigarh, a thoroughly well-planned city, because of the technical capabilities and far-sightedness of the French architect, Le Corbusier, who was commissioned to design a new township with modern amenities and well-planned infrastructure. It is also agreed upon by various historians that the blueprint of Chandigarh was designed by Corbusier right here in Shimla's US Club.

The central part of New Delhi is another best example of the city planning which was jointly designed by Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker. Without such visionary expertise, the city may get comparatively improved but it seems improbable that it will make Shimla 'smart'.

b) The decision making body of Shimla Smart City Limited is made of the people with additional charge in the government offices. The routine nature of working in the government system reduces the innovativeness and the ability to think out of the box gradually languishes. Such machinery is good enough to run the show but hardly adequate to possess the acumen to think and dare to bring drastic change as and when needed.

c) Keeping in view the unpleasant facade of the majority of the parts of Shimla city, there is a need to bring a thorough transformation, especially in terms of infrastructure. Public resentment is inevitable, if the development plan is chalked out with a holistic perspective. To deal with such situations, there is a dire need to have the courage to take the necessary initiatives and face the likely agitations.

d) The public meetings taking place in the city planning seem purely symbolic which merely are a spectacle for the documentaries or the pro-cultural obligations. The ward committees are formed by the counselors by involving a few known people unlike the Gram Sabhas in panchayats. This platform does not invite common residents' opinions. The voice of Resident Welfare Societies and other Community Based Organisations (CBOs) need to be given due emphasis as these group represents the majority of the localities. No effective involvement of the city people will be seen anywhere until they are sensitised to accept the reforms, otherwise, all the actions at the Smart City level will remain isolated.

e) The timeline and accountability are the most important aspects of any project. Majority of our ambitious projects of national importance used to remain in limbo for an undefined period, for countless reasons. It is to be kept in mind that the authorities responsible for the tasks, if changed frequently, will hamper the progress of the project and no one can or will be held accountable.

The foundation of Smart City in perspective of the people is based on the broader roads, planned and the regulated transportation system, ease of getting day-to-day services at the doorsteps; park for children in each locality; children and senior citizen-friendly public facilities, and allied infrastructure. A separate medical facility for each segment of around 5,000 population; accessible educational facilities; regular maintenance and cleanliness of the city; conscious efforts to increase the green cover in Shimla, an essence that we cherish so much; availability and access to small libraries, for the education and leisure, along with common interaction places; uninterrupted water and electricity, effective law & order and safe environment, etc.

The Smart City in the perspective of tourists and other population, apart from the above, includes all new and bigger buildings, beautiful landscapes, information and knowledge centres like museums, recreation centres, and multiple spots of charm, beauty, fun, good dining spots, thrill and adventure, including a community swimming pool.

Shimla has all the potential but needs to be explored with different eyes and mindset. Many existing heritage sites exist but we know nothing about them, such as the home of A.O. Humes, the founder of Congress, but its location is unknown.

Recently, during my trip to the USA, I had a chance to visit National Postal Museum in Washington DC, which was impressively well-planned and nicely marketed; there is no doubt that we can also create a number of such monuments here too. Shimla is known for pedestrian path and a number of such paths need to be identified and beautified. The pedestrian paths have been USP of Shimla city and the city should be known for more such paths giving fragrance of blooming flowers.

The new wards identified and likely to be identified should start with the proper town planning layout provisioning roads, schools, drainage, gymnasium, parks and other. No human activity should be promoted in the unplanned area.

The areas adjoining to the city should be treated as buffer and need to be brought under town planning as later or sooner that area can be easily merged with the main city. No unplanned activities should be encouraged in such areas also. The infrastructure needs to be planned as per the available technical standards including proper consideration of slopes and gradients.

The challenges of Shimla include the broadening of the narrow, traffic-congested roads within the city by pulling down the adjoining houses which lack proper planning and pose a great danger during the time of any high-intensity earthquake; demolishing all non-heritage old buildings and creating earthquake-resistant structures is highly essential. Inviting experts and industries to manage the civic amenities and finally making residents the contributors towards Smart City planning in terms of sharing knowledge and experience, Owning some of the public utility service delivery systems, cooperating with the regulatory bodies and bringing IT and other technologies in place, in lines with the public-friendly technologies available in European and America-like countries, etc. Are need of the hour.

This mammoth-sized task is complicated nevertheless crucial; working on this model will yield impressive results and its contributors will be remembered by the posterity as long as the Smart City Shimla will remain in existence. The 3D Model of the proposed SMART City can be displayed in each ward and all prime locations. This will not only educate the people of Shimla about the futuristic view of the city, but it will also fix the accountability of the responsible authorities.

Dr. L.C. Sharma
Editor-in-Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

देश और धर्मशाला में अंतर होता है

जिस घर में रहते हैं उसी की दीवार नहीं तोड़ी जाती

ऐसा लगता है कि देश में सरकार के किसी भी निर्णय को विपक्ष न तो स्वीकार करने के पक्ष में है और न ही शांति से बैठने का पक्षधर है। विपक्ष की भूमिका हमेशा से ही सराहनीय और सरकार से भी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक भी है कि सरकार के साथ विपक्ष हमेशा मज़बूत रहे ताकि जनता की आवाज़ को पुरज़ोर तरीके से सरकार के सामने रख सके और सही–ग़लत पर भी सरकार को सतर्क करता रहे। लेकिन वर्तमान में देश में जो घटित हो रहा है उससे लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों की अपने–अपने स्तर पर लोगों को समझने में भूल तो कर ही रहे हैं। इसमें विपक्ष की भूमिका पर तो सवालिया निशान उठाना यहां हमारी ज़िम्मेवारी बनती है। देश के आंतरिक मामलों पर किसी भी मुद्दे पर विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो बहस करे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन जहां देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो वहां क्या पक्ष क्या विपक्ष, देश की सुरक्षा और हित ही सर्वोपरी होना चाहिए। भारत में इसे किसी भी संदर्भ से जोड़कर देख लो, यहां देश के लिए हमारी प्राथमिकताओं का आकलन अलग–अलग परिभाषित होता है ।

सी ए ए को लेकर सरकार के निर्णय पर आज देश में अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। विरोध का ये तरीक़ा ऐसा है जैसे मानो एक बार फिर से आपातकाल लग गया हो। क्या इस कानून को समझने में भूल हो रही है ? क्या ये कानून देश की एक कौम के नागरिकों के विरुद्ध है ? क्या इससे किसी की नागरिकता को ख़तरा पैदा हो गया है ? क्या जो विरोध कर रहे हैं उन्हें देश की अस्मिता और अखंडता का ज्ञान है ? क्या नागरिकता संशोधन कानून के बारे में संपूर्ण जानकारी है ? इन प्रश्नों को लिखते हुए भी इसलिए हंसी आ जाती है कि बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि विरोध और तोड़फोड़ में वो क्यों शामिल है ? उन्हें कौन प्रायोजित कर रहा है और किसके ईशारे पर देश में आगजनी की जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर जानकर भी देश में इस प्रकार का माहौल चिंतनीय है ।

विरोध से होते हुए देश तोड़ने तक

शिक्षा के पुराने संस्थान जवाहर लाल यूनिवर्सिटी एक ओर तो देश के दुद्धिजीवियों की जनक भी रही है वहीं आज इसे देशद्राहियों और लोकतंत्र के परखच्चे उड़ाने वालों की पनाहगार के रुप में जनता देख रही है। इसे विडंबना कहा जा सकता है कि इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान को टुकड़े–टुकड़े गैंग के नारों और देशविरोधी गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है। कन्हैया और उस वर्ग का क्या करें जिन्होंने सरेआम आज़ादी के नारे लगाकर देश में ही विद्रोह का माहौल तैयार करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी और अब मूलतः बिहार के निवासी शरज़ील ने फिर से एक विवादित विडियो में देश को तोड़ने और बेहद आपत्तिजनक ब्यान देकर आग सुलगा दी है। एक विडियो में इस व्यक्ति ने कहा कि आसाम को भारत से अलग करने के लिए किस प्रकार वो देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देगा। क्या इस प्रकार के ब्यान देने और धूम से विडियो इस देश में निकाल कर भड़काना अब आदत बन चुकी है और ऐसा करके हम देश के मान–सम्मान के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसका आसानी से पता चल जाता है।

देश विरोधी ब्यानबाजी करके राष्ट्रीय नेता बन जाओ, खूब वाहवाही बटोरो और प्रसिद्धि को जेब में भरकर संविधान को ठेंगा दिखाओ । यही तो हो रहा है। शाहीन बाग में जो हो रहा है, क्या कोई इसे सही साबित कर सकता है? विरोध का तरीक़ा ही ऐसा है कि जहां ज्ञान, जानकारी सब कुछ शुन्य है और सड़क पर आकर सार्वजनिक स्थान पर कब्ज़ा करके देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना कहां तक न्यायोचित है ? क्या भारत देश में किसी को भी कुछ भी देशविरोधी बातें चौराहे पर करने की खुली छूट हैं ? यहां रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, आंतकवादियों को मारने या फांसी के फैसले पर आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर को भारत से आज़ाद करने के नारे कोई और नहीं इसी मिट्टी में पले–बढ़े और यहीं का खाने वाले लगाते हैं, देश की सरकार के हर निर्णय पर आपत्ति अब आम बात हो चुकी है। किसी एक कौम को भड़का कर आख़िर ये असामाजिक तत्व क्या साबित करना चाहते हैं ? देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं। इतनी आज़ादी कहां से आ गई कि देश की राजधानी में ही बैठकर देश को तोड़ने के लिए भड़काऊ ब्यान दिए जा रहे हैं और योजनाऐं तैयार

की जा रही है। इस पर भी राजनीति हो रही है। शरज़ील की देश विरोधी गतिविधियों को भी रैली कर समर्थन मिल रहा है। इससे बड़ी दुःखद बात और क्या हो सकती है कि हम ये जानते हुए भी कि कुछ बातें राष्ट्रविरोधी हैं और इसी देश के लोग उसका भी समर्थन करते हैं।

भड़काने में क्या आम लोगों का हाथ होता है ? इसमें भी सियासी चाल को समझने की आवश्यकता है। लोगों को लड़ाकर खुद लड्डु खाने वाले कोई और ही होते हैं और लोगों को लड़ाकर स्वार्थ की रोटियां सेंकते हैं। दिल्ली के चुनाव इस बार कई मायनों में याद रखे जाऐंगे। शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो यह बताने के लिए काफी है कि इस देश के सेक्युलेरिज़्म और सर्वधर्मसमभाव के मूलमंत्र को पैरों के नीचे रखने में कोई गुरेज़ नहीं किया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप और दिल्ली में आगजनी....नाक कटाने की क़वायद

ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर भारत–अमेरिका संबन्धों पर दुनिया नज़र गढ़ाऐ बैठी थी और दुनिया के सबसे ताक़तवर राष्ट्र के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे और दिल्ली में ही थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली में ही गोलियां चल रही थी ओर लाशें गिर रही थी। दुकानों, मकानों, गाड़ियों को तोड़–फोड़ा जा रहा था, खून बहाया जा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका इल्म नहीं था, ये तो संभव ही नहीं है। ट्रंप ने भारत की तारीफों के पुल बांधे थे और कहा था कि भारत एक शक्तिशाली देश के रुप में पहचाना जा रहा है। उसी समय असामाजिक तत्व सीएए के नाम पर दिल्ली में भारत की दूसरी तस्वीर पेश कर रहे थे। यह अति दुःखद है कि पुलिस के जवान सहित मौतों का आंकड़ा दहाई की संख्या को छू गया है। इतना ही नहीं एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया जिसमें एक आगजनी कर रहा युवक जवान पर पिस्तौल ताने खड़ा है। ये हम कहां आ गए हैं। विरोध तो हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे लेकिन जो विरोध इस बार सीएए या एनआरसी को लेकर किया गया है इसका आकलन किस तरह से किया जाए, यह दुविधा का विषय है। क्योंकि एक तहर से आधी संख्या तो विरोधियों की यह भी नहीं जानती कि वो पथराव क्यों कर रहे हैं ? सीएए या एनआरसी क्या है, कुछ भी ज्ञान इनको नहीं है। ऐसे में यह कहना ग़लत न होगा कि खेल परदे के पीछे से खेला जा रहा है और उसका मोहरा बनाया गया है उन युवाओं को जिन्होंने मेहनत से कमाई करने के बजाय देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने के ऐवज में कमाई करने की ठानी है। पत्थरों के ढेर और बोरियां भर–भर कर कहां से और कब लाई गई इसका पता तो हमारी पुलिस को भी नहीं वहां। लेकिन यह सब हो रहा है और बहाना है सीएए का। कितना शर्मनाक है कि जो यहां के नागरिक है वो ही विरोध कर रहे हैं सीएए का। सरकार का रुख भी स्पष्ट है कि इस निर्णय से कत्तई भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है, अब गृह मंत्रालय को इसका संज्ञान कड़ाई से लेते हुए समस्या के निदान की ओर भी क़दम उठाने की आवश्यकता है । अमेरिका के साथ भारत के संबन्धों को एक नई दिशा मिलने की ओर यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप भी इसका संकेत दे चुके हैं कि भविष्य में भारत के साथ संबन्धों को और अधिक प्रगाढ़ किया जाऐगा। शीघ्र ही एक बड़ी डील भी होगी जिससे भारत में रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। ये सब शायद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि जिस कार्य को वो हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए ही ट्रंप का ऐसा स्वागत हुआ कि ट्रंप निःशब्द हो गए। भारत की तारीफ में जो कसीदे पढ़े उसे पूरी दुनिया ने सुना। आतंकवाद पर तो पड़ोसी मुल्क़ पाक़िस्तान को खरी–खरी सुना दी। उसी समय हमारी राजधानी में आगजनी से माहौल को बिगाड़ा जा रहा था। इस प्रकार की द्वेषपूर्ण राजनीति का ये स्याह चेहरा भयानक ही कहा जा सकता है। देश की नाक कटाने में उपद्रवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है । विरोध के लिए देश में स्थान चिन्हित है या ऐसी जगह का चयन किया जा सकता है जहां आम जनता को परेशानी न हो और सार्वजनिक संपत्ति को तो तोड़ने को सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यह विरोध शाहीन बाग से दिल्ली के उन सभी स्थलों पर किया गया जहां से जनता भारी परेशानी में आई और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी ख़तरा पैदा हो गया।

देशप्रेम का प्रशिक्षण नहीं होता...ये हमारा डीएनए है

इस सब के पीछे जो सूत्रधार है, उसका पटाक्षेप भी जनता के सामने हो ही रहा है। देश से बड़ा और क्या हो सकता है ? इसे समझने के लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है ? देश प्रेम के रक्तबीज तो हमारे डीएनए में है । इसे स्वभावतः समझना होगा। राजनैतिक कलह और मुद्दें सदियों से होते रहे हैं। विरोध करना सभी का नैतिक अधिकार है । लेकिन जहां देश की अस्मिता और सम्मान जुड़ जाता है वहां समझौता नहीं किया जा सकता है । आज जो भी देश में सीएए के नाम पर हो रहा है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। देश की संपत्ति को तोड़ने, आगजनी करने, दंगे फैलाने के लिए उसी पीढ़ी के कांधों का उपयोग हो रहा है जो इस देश का भविष्य तय करेगी। हिंदु–मुस्लिम या अन्य कोई भी कौम देश से बड़ी नहीं है । इसकी गोद में हम जन्में, पलें, रोजीरोटी से जीवनयापन तक सब कुछ करते हैं, उसे इस प्रकार गाली देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है । देश के प्रति आदर और सम्मान के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती । यहां हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने के साथ ही प्रतिदिन हमारे जवान सीने पर गोली खाते हैं । क्योंकि निज देश से प्रेम ही उनका धर्म है । भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस, गांधी, उधम सिंह, रानी झांसी आदि देशप्रेमियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि उन्हें क्यों और कैसे देश से प्रेम करना है । इस माटी में जन्म लेने वाला हर इंसान इसे अपने रक्त में लेकर ही पैदा होता है । ऐसे में वर्तमान की ये घटनाऐं दुखी तो करती ही है ।

देश को धर्मशाला न बनने दे...यह तीर्थ है

1947 में एक सियासी भूल ने उस समय भी विकट परिस्थितियों को जन्म दिया था और उसका ख़ामियाज़ा आज भी देश भुगत रहा है। किंतु आज इस देश में हिंदु–मुस्लिम आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं तो सियासीदारों को यह समझना चाहिए कि कौमी फूट से मात्र विनाश ही होता है। देश के लिए इसका कोई लाभ नहीं है । देश में बाहरी पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थी अथवा घुसपैठिऐं इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं । इसलिए यह कानून उनके लिए तो ख़तरा है ही लेकिन जो इस देश का नागरिक है उसे इससे कोई ख़तरा नहीं है यानि उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा है। फिर भी इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि यह भारत के टुकड़े कर देगा जबकि सच्चाई वास्तविकता से दूर है । यह देश तीर्थ तो हो सकता है लेकिन धर्मशाला नहीं है कि जो भी चाहे, जैसे भी चाहे यहां आकर रहने लग जाए। इसे धर्मशाला बनने से बचाने की आवश्यकता है ही साथ ही देश की संसद में पारित कानूनों को सम्मान देने की भी आवश्यकता है। ये परंपरा एक तुच्छ संदेश से अधिक और कुछ नहीं हो सकता कि संसद में पारित कानून को संसद की दहलीज़ से बाहर आते ही उसका विरोध शुरु कर दिया जाए । विरोध भी ऐसा कि देश की संपत्ति को तोड़ने के साथ ही एक–दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए।

यहां यह कहना ग़लत न होगा कि विरोध सीएए का नहीं शायद.....ये विरोध आने वाले बिलों और कानूनों को लेकर है जिससे ख़ौफ का माहौल तैयार किया जा रहा है और समुदाय विशेष को भड़काने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

कविता

पाठक की कलम से

माँ

तेरे प्यार को मै शब्दों मे क्या ब्यां करूँ ,
कोशिश करता हूँ तो आँख भर आती है,
तुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाती है ।
जन्म दिया और चलना तूने सिखाया,
दुनियादारी से भी वाकिफ तूने करवाया ,
गलतियां तो मैंने की होंगी हजार,
माँ, पर तूने मुझे हमेशा दिया प्यार ।
तेरी हर डाँट पर मैंने होगा तुझे कोसा ,
फिर भी तूने मुझे गलती करने से रोका,
भगवान का घर में जब भी नाम आया,
मैंने तुझे हमेशा उस रूप मे पाया ।

माँ

तेरे प्यार को मै शब्दों मे क्या ब्यां करूँ ,
कोशिश करता हूँ तो आँख भर आती है,
तुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाती है ।
आंधी तूफान ने जब भी मेरा रास्ता रोका,
जिंदगी ने जब भी मुझे दिया धोखा,
काँच की तरह जहाँ मै बिखर जाता,
तेरा प्यार ही मुझे वहाँ जीत दिलाता ।
मै मूर्ख सोचता ये परिणाम है मेरी मेहनत का,
पर असल में ये होता तेरी रहमत का,
धन्यवाद है उस भगवान का जिसने तुझे बनाया,
वरना प्रेम के सागर से मै रह जाता पराया।

माँ

तेरे प्यार को मै शब्दों मे क्या ब्यां करूँ ,
कोशिश करता हूँ तो आँख भर आती है,
तुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाती है ।
मेरी हर खुशी पर जश्न तूने मनाया,
आज तक अपने हर दुख को मुझसे छुपाया,
समझ ना पाया मै कभी भी इस बारे में,
क्योंकि खुशी ही छिपी थी तेरे हर इशारे में ।
दुःख को छिपाया तूने कुछ इस तरह,
मछली के लिए बाहर की दुनिया जिस तरह,
दुःख से मै आज भी हूँ अनजाना,
तेरी प्रेम की ममता को अब मैंने पहचाना ।

माँ

तेरे प्यार को मै शब्दों मे क्या ब्यां करूँ ,
कोशिश करता हूँ तो आँख भर आती है,
तुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाती है ।
सूरज दिखा पर उजाला देख ना पाया,
माँ तेरे प्यार को मै कभी समझ ना पाया,
प्यार है तेरा या रात की चाँदनी,
रोज गहरी होती जा रही इसकी रौशनी ।
आज आँख खुली तो चेहरा तेरा नजर आया,
लगता है बुराई से पर्दा आज ही उठ पाया,
समझ गया मैं की मेरी ज़िंदगी तू है,
माँ तू मुझसे इतना प्यार करती क्यों है ?

माँ

तेरे प्यार को मै शब्दों मे क्या ब्यां करूँ ,
कोशिश करता हूँ तो आँख भर आती है,
तुझसे अब ये दूरी सही नहीं जाती है ।।

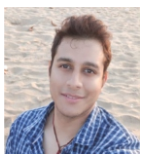

आशित गुप्ता
पुणे / कोमली बैंक शिमला, हि.प्र.

बजट सत्र

शहर के बाद गांवों को भी सीवरेज से जोड़ने की योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के शहरी क्षेत्रों के बाद गांवों को भी सीवरेज योजना से जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा के एक गांव का इसके लिए सर्वे किया जाएगा। उसके बाद योजना को शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

नाचन के विधायक विनोद कुमार के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि अभी चार ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग से इस कार्य के लिए डिपॉजिट दिया गया है। प्रदेश के ऐसे गांव जहां घनी आबादी है, वहां पर योजना को शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों से एक-एक गांव का नाम बताने की अपील भी की। सुंदरनगर के विधायक राकेश जमवाल ने क्षेत्र के चार वार्डों को मल प्रवाह से जोड़ने की मांग उठाई। उन्होंने कि सीवरेज कनेक्टिविटी न होने से सुकेती खड्ड से सतलुज में गंदगी जा रही है। एनजीटी इसकी मानीटरिंग कर रही है। इस पर जल शक्ति मंत्री ने विधायक को स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में इसका प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।

हिमाचल विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने विपिन परमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल विधानसभा के 17वें अध्यक्ष का विपिन सिंह परमार ने पदभार संभाल लिया। इस बार के बजट सत्र में उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने परमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और राकेश पठानिया ने उनके नाम का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। मुख्यमंत्री ने कहा परमार का अध्यक्ष बनना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि परमार के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया है। अन्य विभागों की अपेक्षा स्वास्थ्य महकमे में बहुत काम हुआ है।

हिमाचल में डॉक्टरों के 367 पद खाली, एम्स में इस माह से एमबीबीएस की कक्षाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विभिन्न अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 367 पद खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संदासु में तीन पद स्वीकृत और भरे गए हैं। नागरिक अस्पताल क्वार में एक्सरे मशीन है। रेडियोग्राफर न होने से सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने यह जानकारी रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्ट के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। हिमाचल के बिलासपुर एम्स का निर्माण कार्य सितंबर, 2021 तक पूरा होना प्रस्तावित है। जुलाई, 2020 से एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी ज्वालामुखी विधायक रमेश ध्वाला के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी इंडिया, लिमिटेड) के मध्य एमओयू (ज्ञापन) हुआ है।

एचपीयू से स्नातक करने वालों को डिवीजन सुधारने का गोल्डन चांस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्ष 2000 के बाद स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को डिवीजन सुधारने के लिए गोल्डन चांस देने का फैसला लिया है। विवि प्रशासन ने 4 फरवरी की ईसी की बैठक में इस मसले पर चर्चा की थी। इसके बाद फैसला लिया था कि 2000 के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री करने वाले जिन विद्यार्थियों के अंक कम हैं, वे अपनी डिवीजन बढ़ाने के लिए परीक्षाएं दे सकते हैं। विवि के कुलसचिव घनश्याम चंद की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं।

अप्रैल 2020 में होने वाली परीक्षाओं में विद्यार्थी पेपर दे सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम 2012–13 का तय किया है। विद्यार्थियों को 5000 रुपये फीस प्रति सेमेस्टर देनी होगी।

कई बार अंक कम होने के कारण युवा नौकरी के लिए न्यूनतम पात्रता हासिल नहीं कर पाते, इसलिए विवि प्रशासन के समक्ष डिवीजन इंप्रूव करने का मौका देने की मांग बार-बार उठ रही है।

अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होगी स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती परीक्षा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में स्कूल प्रवक्ता (न्यू) की भर्ती परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। राज्य लोकसेवा आयोग के पत्र पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट की है। निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार ने आयोग को राजनीति शास्त्र व इतिहास की परीक्षा दोनों भाषाओं में लेने को कहा है। आयोग को भेजे पत्र में उन्होंने 23 फरवरी को हुई कामर्स की परीक्षा को रद्द न करने की सिफारिश भी की है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रवक्ता की भर्ती में पहले ही बहुत देरी हो गई है। ऐसे में परीक्षा रद्द होने से और देरी होगी। सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में स्कूल प्रवक्ता (न्यू) की परीक्षाएं लेने के विवाद के बाद आयोग ने नोटिस जारी कर आगामी आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निदेशालय से स्पष्टीकरण मांगा था। अब निदेशालय ने जवाब तैयार कर आयोग को भेजा है।

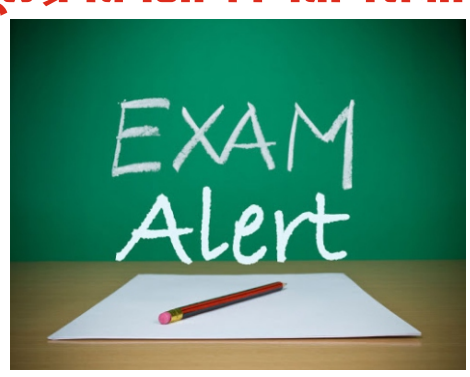

अब आयोग अंतिम फैसला लेकर नया नोटिस जारी करेगा। स्कूल प्रवक्ता के राजनीति शास्त्र की परीक्षा 14 मार्च और इतिहास की परीक्षा 23 मार्च को प्रस्तावित है। स्कूल प्रवक्ता इतिहास के 47 पदों के लिए 3050 और राजनीति शास्त्र के 40 पदों के लिए 5282 आवेदन हुए हैं। अनुबंध आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रतिमाह 14,500 रुपये तनख्वाह मिलेगी। स्कूल प्रवक्ता की भर्ती में सामान्य श्रेणी के आर्थिक तौर पर कमजोर आवेदकों को भी इस भर्ती में आरक्षण मिलेगा।

निगरानी में रखे थाईलैंड के पांच पर्यटक भागे, निर्वासित तिब्बती सरकार का सम्मेलन स्थगित

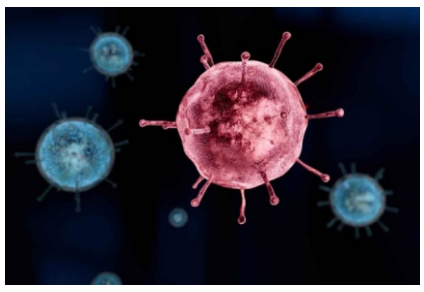

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पर्यटन नगरी धर्मशाला के एक होटल से थाईलैंड के पांच पर्यटक भाग गए। इन विदेशी पर्यटकों को स्वास्थ्य विभाग ने 5 मार्च को सुबह ही 28 दिन तक निरागनी में रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन शाम करीब छह बजे पांचों पर्यटक होटल छोड़कर भाग निकले। होटल प्रबंधन ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। वीरवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएमओ कांगड़ा डॉ. गुरदर्शन गुप्ता की अगुवाई में होटल पहुंची। सीएमओ ने बताया कि ट्रेवल हिस्ट्री के अनुसार पांचों पर्यटकों को 28 दिन निगरानी में रहने की हिदायत दी गई थी। पांचों पर्यटक संवेदनशील देश से पहुंचे थे। निर्वासित तिब्बती सरकार का सम्मेलन सीगित कोरोना वायरस के चलते निर्वासित तिब्बत सरकार ने दो से चार अप्रैल तक होने वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्थगित कर दिया है। धर्मशाला में दो से चार अप्रैल तक तिब्बेतन संघ का शिखर सम्मेलन होना था। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रवक्ता तेसवान गयालपो ने बताया कि हालात सामान्य होने के बाद सम्मेलन का शेड्यूल जारी करेंगे।

हिमाचल आर्थिक प्रदर्शन 2019–20

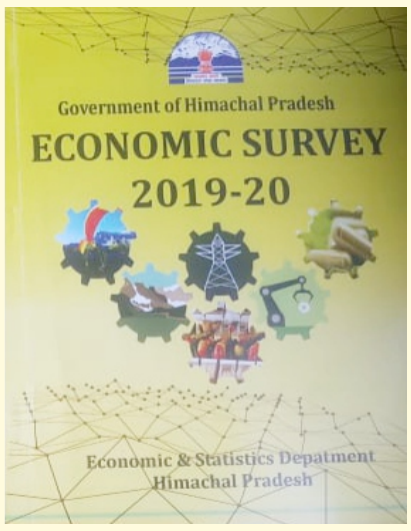

प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019–20 के अन्तर्गत् वृद्धि की दर लगभग 5.6 प्रतिशत रहने की सम्भावना है जबकि 2018–19 में 1,17,851 करोड़ की तुलना में स्थिर कीमतों पर कुल जी.एस.डी.पी. का अनुमान 1,24,403 करोड़ है। मौजूदा कीमतों पर जी.एस.डी.पी. 2018–19 के अन्तर्गत् 1,53,845 करोड़ के विरुद्ध लगभग 1,65,472 होने की सम्भावना है। 2019–20 के अन्तर्गत् 5.6 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रुप से प्राथमिक क्षेत्र का 9.3 प्रतिशत तथा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवा का क्षेत्र 7.7 प्रतिशत है। द्वितीय क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बागवानी उत्पादन में 42.82 प्रतिशत की वृद्धि के कारण समग्र प्राथमिक क्षेत्र में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो अंततः 5.6 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2019–20 के लिए वास्तविक रुप से प्रति वर्ष 2011–12 कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,46,268 के स्तर को प्राप्त करने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2018–19 में 1,39,469 के स्तर से 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो 2018–19 के लिए पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार 1,83,108 थी, वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत् 1,95,255 तक बढ़ने की सम्भावना है, जिससे लगभग 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पांच सालों में 2.62 घटा कृषि और संबद्ध क्षेत्र का भाग

वर्तमान मूल्य पर राज्य के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का भाग 2014–15 में 15.35 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 12.73 प्रतिशत हो गया।

पर्यटन 2019 में 17.21 मिलियन पर्यटक पहुंचे हिमाचल

हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2004 में 6.55 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 17.21 मिलियन हो गई। वर्ष 2018 में गेस्ट हाउस / होटल की संख्या 2016 में 2,784 से बढ़कर 3,382 हो गई तथा बिस्तर की संख्या क्षमता 2016 में 75,918 से बढ़कर 2018 में 91,223 हो गई।

ऊर्जा

अब तक लगभग 10,596.27 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन हिमाचल प्रदेश राज्य में 27,436 मेगावाट की अनुमानित जल क्षमता है, जिसमें से 24,000 मेगावाट का ही आकंलन किया जा सका है, जबकि विभिन्न सामाजिक सरोकारों की रक्षा करके हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संतुलन बनाए रखने का निर्णय लिया है। लगभग 24,000 मेगावाट की कुल दोहन योग्य क्षमता में से, 20,912 मेगावाट की क्षमता के लिए पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत् आवंटित की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र में रुझान

सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन वर्ष 2017–18 से वर्ष 2018–19 में थोड़ा कम हुआ है। वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान हर वर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि यह वर्ष 2014–15 में 26.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 29.79 प्रतिशत हो गया है।

मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014–15 से मुद्रास्फीति में कमी देखी जा रही है। वर्ष 2019–20 में हेडलाईन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-कंबाइंड (CPI-C) मुद्रास्फीति 2.5 फीसदी थी जबकि वर्ष 2014–15 में 6.2 फीसदी थी। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति में वर्ष 2015–16 और वर्ष 2018–19 के बीच वृद्धि देखी गई है, यह वर्ष 2018–19 में 4.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019–20 के दौरान 1.5 प्रतिशत हो गई।

सामाजिक सेवाओं पर व्यय में रुझान

समावेशी विकास और रोजगार के लिए सामाजिक अवसंरचना में निवेश पूर्व-आवश्यकता है। सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 का एक प्रमुख आकर्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2014–15 में 7,973 करोड़ से बढ़कर 2019–20 बजट अनुमानद्ध में 15,156 करोड़ हो गया।

राजकोषीय विकास

राज्य सरकार प्रशासन और विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, गैर-कर राजस्व, केन्द्रीय करों का भाग और केन्द्र सरकार से अनुदान के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाती है। वर्ष 2019–20 बीई के बजट अनुमानों के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां 33,747 करोड़ हैं, जबकि वर्ष 2018–19 में 31,189 करोड़ के मुकाबले आरई 8.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

नाडा ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर लगाया चार साल का बैन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमित दहिया ने साल 2019 में राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चौंपियनशिप के दौरान डोप नमूने के लिए अपनी जगह किसी और को भेज दिया था। नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने अमित दहिया पर चार साल का बैन लगा दिया है। नाडा ने अमित दहिया के मामले को 09 जनवरी 2020 को एडीडीपी (अनुशासनात्मक पैनल) के पास भेज दिया। एडीडीपी ने अब अमित दाहिया को अस्थाई निलंबन की तारीख से चार साल तक निलंबित करने का फैसला सुनाया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही कैट के दायरे में लाया जाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही कैट के दायरे में लाया जाएगा दिल्ली में कैट की अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वे कैट के नोडल विभाग के प्रभारी भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कैट के पास जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से संबंधित मामलों और मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा। जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई कर रहा है। राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने हाल ही में कहा कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में कैट की विशेष पीठ गठित की जाएगी।

अटल भूजल योजना: विश्व बैंक भूजल प्रबंधन हेतु देगा 45 करोड़ डॉलर का ऋण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व बैंक भूजल प्रबंधन हेतु देगा 45 करोड़ डॉलर का ऋण देगा। अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) का उद्देश्य भागीदारी भूजल प्रबंधन से जुड़े संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। एबीएचवाई को राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहायता मिलेगी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2020

द रीव टाइम्स ब्यूरो

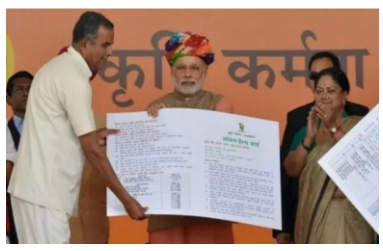

19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने में राज्यों का सहयोग करना है। भारत सरकार किसानों के लिए इस दिन विभिन्न जागरूकता एवं सूचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर जोर दिया कि अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो कृषि उत्पादन में बाधा आएगी।

विलुप्त होने की कगार पर पक्षियों की कई प्रजातियां: रिपोर्ट

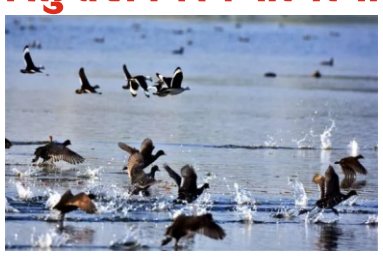

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है। प्रवासी जीवों पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सीओपी-13 में 'स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोटर्स 2020' के जरिए पक्षियों के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तेजी से गिरावट वाले पक्षियों में शिकारी पक्षी, प्रवासी समुद्री पक्षी पिछले दशकों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आम धारणा के विपरीत 25 साल से अधिक समय में गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है। मोर की संख्या बढ़ रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक गिद्ध की संख्या पहले घट रही थी, लेकिन अब यह बढ़ने लगी है। गौरैया की संख्या दिल्ली, मुंबई समेत छह मेट्रो शहरों में हल्की गिरावट आई है।

महिलाओं को सेना में मिला स्थायी कमीशन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी आयोग के केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमान देने हेतु बाध्य है। शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का लक्ष्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की सहायता करना था। स्थायी कमीशन दिये जाने का मतलब यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब सेवा-निवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं।

सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 5वां स्थान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-2019 का यह डेटा आइक्यू एयर विजुअल के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक साल तैयार होती है। नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि विश्व के तीस सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 21 भारत के हैं। विश्व के कई देश वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जारी की गई यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली के कुछ इलाकों में नवंबर 2019 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 को पार कर गया था।

महंत नृत्य गोपाल दास बने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महंत नृत्य गोपाल दास को हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं, विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव बनाया गया। नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के कहौला गह्वर में हुआ था। उनके मठ 'मणिराम छावनी' में पांच सौ साधुओं की जमात स्थाई तौर पर रहती है। चंपत राय ने अपने करियर की शुरुआत भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता से की थी।

श्री रामायण एक्सप्रेस का आगाज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह ट्रेन भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। आईआरसीटीसी के मुताबिक बुकिंग पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ के अनुसार होगी। इस यात्रा के लिए इच्छुक पर्यटक दिल्ली से सफदरजंग, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इस टूर में यात्रियों को होटल, धर्मशाला और स्थानीय सफर के लिए बस सेवा भी मिलेगी। श्रीलंका में रामायण सर्किट के दर्शन के इच्छुक पर्यटकों से प्रति व्यक्ति 37,800 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इस आयोग का गठन करती है। इस आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था। आयोग का पुनर्गठन तीन साल हेतु किया जाता है। इससे पहले 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास एवं देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ने की भारत यात्रा, नमस्ते ट्रम्प में भाग लिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद, गुजरात का दौरा किया। अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप तथा बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल थीं। इसके अलावा उनके वरिष्ठ सलाहाकार जेरेड कुशनेर भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रंप अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम भी गये। डोनाल्ड ट्रम्प ने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका कट्टरवाद के खिलाफ साथ हैं। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ रहे रहेंगे और लड़ेंगे। देश के लिए जो खतरा है उसका हल मिलकर निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने वहां के विकास में बड़ा रोल निभाया है।

24 फरवरी को मनाया गया सेंट्रल एक्साइज दिवस 2020

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हर साल 24 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाता है। इस दिवस का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड, केंद्र सरकार के लिए एक प्राथमिक कर संग्रह एजेंसी होने के नाते, इस दिवस को अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के उद्देश्य से भी मनाता है। इसके अलावा यह दिवस माल निर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देशवासियों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व को बताना भी है।

घोंघे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति तापमान-संवेदनशील प्रजातियों के परिवार का हिस्सा है। इसे क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेथथुनबेर्गे नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा के प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया। पत्रिका बायोडायवर्सिटी डेटा में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि घोंघे की यह प्रजाति कैनेओगैस्ट्रोपोडा (Caenogastropoda) समूह की है। यह प्रजाति भूमि पर रहती है और सूखे, अत्यधिक तापमान में उतार - चढ़ाव और वनों की कटाई से प्रभावित हो सकती है।

नीदरलैंड्स में नेचुरल बायोडायवर्सिटी सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक घोंघे की नई प्रजाति ब्रुनेई में कुआला बेलांग फील्ड स्टडी सेंटर के करीब पाई गई।

नेशनल वॉर मेमोरियल की पहली वर्षगांठ मनाई गई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इस युद्ध स्मारक का पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ था उसके बाद से अब तक लगभग 21 लाख लोगों ने यहां विजिट की है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन का पहला सालगिरह समारोह आधिकारिक तौर पर 22 फरवरी 2020 को तीनों सेनाओं के बैंड प्रदर्शन के साथ शुरू किया गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल अथवा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन 25,942 सैनिकों के नाम उकेरित किये गये हैं।

वास्तुकला की दृष्टि से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गोलाकार आधार के मध्य में स्थापित एक स्तंभ है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन ने चार साल पूरे किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन, लोकेशन प्लानिंग पर आधारित क्लस्टर विकास मॉडल है। यह देश भर में ग्रामीण समूहों की पहचान करता है जहां शहरीकरण के बढ़ते संकेत जैसे कि शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि और शहरीकरण के अन्य लक्षण पाए जाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना है। यह बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर और अच्छी तरह से संगठित ग्रामीण समूहों का निर्माण करके इन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन प्रदान करने के लिए काम करता है।

भारत बना दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। यह जानकारी अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट से दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी पिछले साल 2.94 लाख करोड़ डॉलर (209 लाख करोड़ रुपए) के स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया के तेजी से बढ़ते सेक्टर में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पिछले 25 सालों में तेजी से वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2.83 ट्रिलियन डॉलर है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 मनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह दिवस 'रमन प्रभाव' की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज के कारण सीवी रमन को साल 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबल पुरस्कार था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाये जाने का मुख्य उद्देश्य देश में विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी करना है। सीवी रमन का जन्म 07 नवंबर 1888 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी (तमिलनाडु) में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में साल 1907 में असिस्टेंट अकाउटेंट जनरल की नौकरी की।

पांच बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा ने संन्यास की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शारापोवा ने वोग एंड वैनेटी फेयर में आलेख में लिखा कि हाल के सालों में लगातार होने वाली चोटों ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया। मारिया शारापोवा का जन्म 19 अप्रैल 1987 को हुआ था। मारिया शारापोवा फिलहाल 369वीं रैंकिंग पर हैं। मारिया शारापोवा ने अपने लेख लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी टेनिस को दी, टेनिस ने मुझे जिंदगी दी। मैं इसे हर दिन याद करूंगी। उन्होंने 14 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था। उन्होंने साल 2004 में विंबलडन के तौर पर अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

डिजिटल पेमेंट : 2019 में UPI के जरिए हुए 10.8 अरब ट्रांजेक्शन, 18 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन-देन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देश में लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) रास आने लगा है। इसी का नतीजा है कि बीते साल 2019 में यूपीआई के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा तेजी आई है। वर्ल्डलाइन एनुअल इंडिया डिजिटल पेमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। UPI के बाद डेबिड कार्ड, आईएमपीएस और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा किया गया। पिछले तीन साल में यूपीआई ट्रांजेक्शन में औसतन 188 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इससे ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़कर 10.8 अरब पहुंच गई है। UPI को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। साल 2019 में UPI डेबिड कार्ड, आईएमपीएस और क्रेडिट कार्ड से कुल मिलाकर 20 ट्रिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए गए हैं। इन 54 खरब से ज्यादा रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है।

एक महीने में हुए 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक महीने में 100 करोड़ ट्रांजेक्शन के आंकड़े को भी 2019 में पार कर लिया है। सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन के लिए किया गया है। इसके बाद पर्सन टू मर्चेंट का नंबर आता है। यूपीआई के जरिए 2019 में 18,36,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है, जो साल 2018 के मुकाबले 214 फीसदी ज्यादा है।

कोरोना वायरस का खौफ : पांच दिन में दुनियाभर के 500 अमीरों की नेटवर्थ 32 लाख करोड़ रुपए घटी, भारत के आम बजट से ज्यादा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- टॉप-10 में सभी लूजर्स विदेशी, नेटवर्थ में 5.81 लाख करोड़ रुपए की कमी
- अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की नेटवर्थ सबसे ज्यादा 85 हजार करोड़ रुपए घटी

चीन के बाद आधी से ज्यादा दुनिया में फैले कोरोना वायरस की मार दुनियाभर के अमीरों पर भी पड़ रही है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट का माहौल है। इस कारण दुनियाभर के अमीरों ने नेटवर्थ में भी कमी आई है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, पिछले सप्ताह के पांच कारोबारी दिवस में विश्व के 500 अमीरों के नेटवर्थ में 444 बिलियन डॉलर यानी करीब 32 लाख करोड़ की कमी आई है।

दुनिया के टॉप-3 अमीरों की नेटवर्थ 2.16 लाख करोड़ घटी

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, बीते सप्ताह दुनिया के तीन सबसे अमीर व्यक्तियों अमेजन डॉट कॉम के संस्थापक जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और एलवीएमएच के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नाल्ट की नेटवर्थ में 30 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.16 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है।

रिसर्च : डेयरी मिल्क ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को 80% तक बढ़ा सकता है, 53 हजार महिलाओं पर शोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- डेयरी के दूध से ब्रेस्ट कैंसर का संभावित कारण इसमें मौजूद सेक्स हार्मोन कंटेंट हो सकता है
- शोध के मुताबिक, सोया दूध को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें तो खतरा कम हो सकता है

शोधकर्ताओं का कहना है कि डेयरी के दूध कम मात्रा में लेने से भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यह खतरा 80 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। हालांकि, यह दूध के सेवन पर निर्भर करता है। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी से जुड़े गैरी ई. फ्रेजर ने कहा- इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डेयरी दूध पीने के कारण महिलाओं में

ब्रेस्ट कैंसर होता है। प्रतिदिन 1/4 से 1/3 कप डेयरी दूध का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के स्टडी के लिए 53,000 उत्तर अमेरिकी महिलाओं के आहार का मूल्यांकन किया गया। इनमें से सभी शुरू में कैंसर से मुक्त थीं। आठ साल तक महिलाओं पर शोध किया गया।

शोधकर्ताओं ने कहा- प्रतिदिन एक कप दूध पीने से संबंधित जोखिम 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। वहीं, प्रतिदिन दो से तीन कप पीने वालों के लिए जोखिम बढ़कर 70 से 80 प्रतिशत हो जाता है। स्टडी के दौरान महिलाओं के आहार का 24 घंटे मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही उनके जनसांख्यिकी, ब्रेस्ट कैंसर का पारिवारिक इतिहास, शारीरिक गतिविधियां, शराब की खपत, हार्मोनल और अन्य दवाओं का इस्तेमाल, प्रजनन और स्त्री रोग संबंधी बातों का ध्यान रखा गया।

अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो बोले- राष्ट्रपति ट्रम्प का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत को दिखाता है

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारतीय दौरे से वापस लौटने के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया ट्वीट लिखा- लोकतांत्रिक परंपराएं हमें जोड़े रखती हैं, राष्ट्रपति ट्रम्प की अगुआई में यह साझेदारी और मजबूत होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की दो दिन की भारत यात्रा को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शानदार और ऐतिहासिक बताया है। पोम्पियो ने ट्रम्प के अमेरिका लौटने पर ट्वीट किया। इसमें लिखा, "राष्ट्रपति ट्रम्प का दौरा यह दिखाता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम है।"

पोम्पियो ने व्हाइट हाउस के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि 'लोकतांत्रिक परंपराएं हमें (भारत-अमेरिका को) एक करती हैं। दोनों देशों के साझा हित हमें जोड़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में दोनों देशों की यह साझेदारी और मजबूत होगी।

कोरोनावायरस : ईरान में अब तक 54 लोगों से ज़्यादा की मौत वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाएगा भारत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- ईरान में 350 कश्मीरी छात्र और सिख श्रद्धालु फंसे, उन्हें वापस निकालने के लिए अधिकारियों से चर्चा जारी
- दक्षिण कोरिया में 376 नए मामले, कुल संख्या 3526 जो चीन के बाद सबसे ज्यादा
- ईरान में कोरोनावायरस से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है।

यहां अब तक संक्रमण के 385 मामले सामने आए हैं। भारत यहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाएगा। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि दोनों देश के अधिकारी इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 350 कश्मीरी छात्र और सिख श्रद्धालु ईरान से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने ईरान से आने-जाने वाली उड़ानें निलंबित कर दी हैं।

उधर, केरल में रविवार को कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज ने दम तोड़ दिया। वह पिछले दिनों मलेशिया से लौटा था और एर्नाकुलम में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। दूसरी ओर, ईरान में एक दिन में कोरोनोवायरस के संक्रमण के 385 मामले सामने आए हैं और 11 मौतें हुई हैं। अब संक्रमितों की संख्या 978 हो गई है और 54 लोग मारे गए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक, हुबेई प्रांत एक दिन में 35 मौतें हुईं, जिसके बाद मृतकों की संख्या 2,870 हो गई। संक्रमण के 573 नए मामले सामने आए। अब कुल संख्या 79,824 तक पहुंच गई है।

हालांकि, जनवरी-फरवरी के मुकाबले संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी आई है। कोरिया के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन द्वारा जारी बयान के मुताबिक, संक्रमण के करीब 90प्रतिशम मामले डायगु में थे, जो कि नॉर्थ ग्यॉन्गसेंग प्रांत में है।

48 घंटे भी नहीं टिक सका अफगान शांति समझौता तालिबान ने फिर शुरु किया हमला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- दो दिनों में टूटा अमेरिका-तालिबान शांति समझौता
- अफगानिस्तान के खोस्त शहर में धमाका, 3 लोगों की मौत

अविश्वास, शक और आधे-अधूरे मंसूबे के साथ किया गया अफगान शांति समझौता 2 दिनों तक भी अफगानियों को शांति मुहैया नहीं कर सका। अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए हुआ शांति समझौता तब लगभग खत्म हो गया जब पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त शहर के फुटबॉल मैदान में धमाका हुआ। इस धमाके में तीन लोग मारे गए। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है।

कतर की राजधानी दोहा में 29 फरवरी को अमेरिका और कतर ने ऐतिहासिक समझौता किया था। इसके तहत, सभी पक्षों की ओर से संघर्ष-विराम किया जाना था। मगर 2 मार्च को ही तालिबान ने युद्ध-विराम की इस संधि को 'आंशिक' तौर पर तोड़ने का ऐलान किया इसके 48 घंटे के भीतर ही खोस्त में धमाका हो गया।

उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका और दक्षिण कोरिया से तनाव बढ़ने के आसार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे कुछ हफ्तों पहले प्योंगयांग ने 'नया सामरिक हथियार' दर्शाने की धमकी दी थी और कहा था कि प्रतिबंध से राहत देने के लिए अमेरिका को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई।

परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया का यह प्रक्षेपण तीन महीने से ज्यादा वक्त के बाद हो रहा है और यह ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के साथ बातचीत अब भी रुकी हुई

है। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने बताया कि ये दो मिसाइलें पूर्वी तट पर वोनसन इलाके से समुद्र के ऊपर पूर्व की ओर दागी गईं और इन्होंने 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तय की।

नासा ने जारी की लाल ग्रह की गुफाओं और ज्वालामुखी की तस्वीर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर जारी की है। इसमें लाल ग्रह की सतह पर एक रहस्यमय छिद्र नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इससे मंगल ग्रह पर जीवन के कुछ सुराग मिल सकते हैं हालांकि इसके लिए अभी अध्ययन की जरूरत है। इस तस्वीर के अलावा नासा ने पावोनिस मॉस नामक ज्वालामुखी की तस्वीर भी जारी की है, जिसकी धूल भरी ढलानों को इसमें दर्शाया गया है।

इस तस्वीर को नासा के मार्स रिकाइंसेस ऑर्बिटर ने वर्ष 2011 में ही भेजा था, जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अब सार्वजनिक किया है। इसके बारे में नासा के वैज्ञानिक रॉबर्ट नेमिरॉफ और जेरी बनेल ने विस्तार से बताया है। नासा ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि इस छेद के आसपास कई सुरक्षित गुफाओं का भी पता चला है, जिनकी लंबाई 35 मीटर और गहराई 20 मीटर तक होने का अनुमान है। वैज्ञानिक अब यह अध्ययन करने में जुट गए हैं कि इस क्षेत्र के चारों तरफ गोलाकार गड्ढ़ा क्यों है। वैज्ञानिकों के एक वर्ग का अनुमान है कि यह गोलाकार गड्ढा एलियंस की मौजूदगी का सुबूत हो सकता है और शायद मानव जाति अब एलियंस के जीवन को उजागर करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है।

हो रही है सबसे ज्यादा खोज

आयरन की अधिकता वाले लाल ग्रह में गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी सौर मंडल के अन्य ग्रहों के मुकाबले वैज्ञानिक यहां सबसे ज्यादा खोज

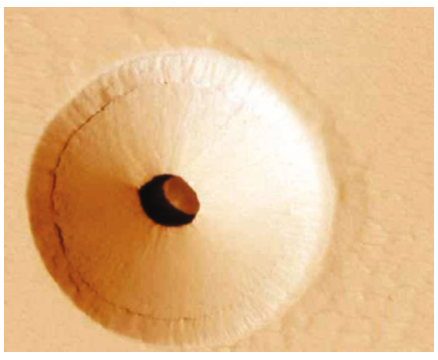

करते हैं। यह ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और इसके वायुमंडल में धूल कणों की अधिकता है। इससे पहले भी नासा के यान ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव के पास एक तस्वीर ली थी जिसमें जमे हुए कार्बन डाईऑक्साइड के पिघलने के कारण एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा था।

जिस मसूद अजहर को पाक बता रहा था 'लापता' उसने अमेरिका-तालिबान डील पर जताई खुशी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

- जैश सरगना अजहर ने अमेरिका को बताया भेड़िया
- कहा- भेड़िए की पूंछ कट चुकी है, दांत किटकिटा रहे

भारत के लिए 'मोस्ट वांटेड' आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है। 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के हाल में हुए सत्र से पहले पाकिस्तान ने अजहर को 'लापता' घोषित कर रखा था। लेकिन अब अजहर ने

अज्ञातवास से बाहर आकर बयान जारी किया है। जिस दिन अमेरिका और तालिबान के बीच डील हुई, उसी दिन अजहर ने तालिबान की पूर्व और मौजूदा लीडरशिप और उसके लड़ाकों को बधाई देते हुए बयान जारी किया।

चीन के तेजी से बढ़ते रथ को धीमा करने के लिए भारत-अमेरिका के साथ हर क्षेत्र में बढ़ा रहा रिश्ते

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पिछले तीन दशकों से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एशिया में उभरती ताकतों को संतुलन के लिए भारत की शक्ति को मान्यता दी है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2000 के दशक के मध्य में नागरिक परमाणु और रक्षा ढांचे के समझौते के जरिए उत्पादक रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्तों को आगे बढ़ाया है। एक सीमा तक दोनों देश एशिया में चीन के बढ़ते उभार को लेकर एकजुट हैं। चीन के तेजी से आगे बढ़ते रथ को धीमा करने के लिए नई दिल्ली अमेरिका के साथ सैन्य और लॉजिस्टिक समझौतों, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, भारत-प्रशांत क्षेत्र पर आम दृष्टिकोण आदि साझेदारी कर रही है।

अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता के चलते निश्चित रूप से यूरोप और मध्य-पूर्व की साझेदारियों पर असर पड़ेगा। परंपरागत रूप से यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रांस अटलांटिक साझेदारी बहुत करीब रही है। ज्यादातर यूरोपीय देश नाटो के भी सदस्य हैं। इसलिए अमेरिका के लिए भारत की निकटता ने वास्तविक रूप से यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों की मदद की है, विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की- दिशा पुलिस स्टेशन
- हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु जितने अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है- चार
- हाल ही में ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, जिस देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है- भारत
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया- काशी-महाकाल एक्सप्रेस
- वह राज्य सरकार जिसने ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को छह-छह करोड़ रुपये देने की घोषणा की- हरियाणा
- ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है- पांच प्रतिशत
- भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री, बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए- सात
- हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गयी है- महाराष्ट्र
- वह देश जो वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें की मेजबानी करेगा- भारत
- दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में जिस देश के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे- चीन
- हाल ही में 'केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण' का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जिस शहर में आयोजित किया गया- नई दिल्ली
- कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और जिस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है- महाराष्ट्र
- हाल ही में आरबीआई ने जितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय 'नई अम्ब्रेला इकाई' स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है-500 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने हाल ही में घोषणा कि जिस केन्द्र शासित प्रदेश को जल्दी ही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के दायरे में लाया जाएगा- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
- सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए जितने वार्ताकारों को नियुक्त किया है- तीन
- हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के जिस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है- दारा शिकोह
- विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये-450 मिलियन डॉलर
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर जितने साल का बैन लगा दिया है- चार साल
- साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है-5.4 प्रतिशत
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जिस दिन मनाया जाता है-19 फरवरी
- स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जिस देश में 79 फीसदी पक्षियों की तादाद घटी है- भारत
- राजस्थान के जिस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया- उदयपुर
- लियोनेल मेसी और जिसने संयुक्त रूप से 'लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2020' का पुरस्कार जीत लिया है- लुइस हैमिल्टन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है- मध्य प्रदेश
- भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किग्रा भारवर्ग के फाइनल में जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया- स्वर्ण पदक
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए जितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया-5,12,860.72 करोड़ रुपये
- वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल 'राड-2' का सफल परीक्षण किया- पाकिस्तान
- जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया- अफगानिस्तान
- हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 'लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट' अवॉर्ड दिया गया है- सचिन तेंदुलकर
- जिसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) नियुक्त किया गया है- बिमल जुल्का
- भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए जिस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है- श्री रामायण एक्सप्रेस
- राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जिसे बनाया गया है- महंत नृत्य गोपाल दास
- सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को जिस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश जारी किया है- राजस्थान
- हाल ही में जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर के नाम पर रखा गया है- रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान
- इथोनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है- हिंदी
- महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जिस दिन मनाई जाती है-19 फरवरी
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तीन दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की जितने नई प्रजातियाँ पाई गई हैं- दो
- हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट-टोऐड गेको की खोज की गई- असम
- भारत में जिस तारीख से भारत यूरो-6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जायेगा-01 अप्रैल
- पांच बार की जिस ग्रैंडस्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है- मारिया शारापोवा
- हाल ही में 'तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन- 2020' का आयोजन जिस शहर में किया गया- नई दिल्ली
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खम्भात शहर में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है- गुजरात
- हाल ही में जो देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है- श्रीलंका
- हाल ही में जिस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी-करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है- पीवी सिंधु
- वह देश जिसके साथ भारतीय वायुसेना के 'इन्द्रधनुष युद्धाभ्यास' का आयोजन किया जा रहा है- इंग्लैंड
- फ्रांस में भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है- जावेद अशरफ
- जानेज जनसा जिस देश के प्रधानमंत्री चुने गये हैं- स्लोवेनिया
- जिस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया है- बिहार
- हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट-2020 के अनुसार जो विश्व का सबसे अमीर शख्स है- जेफ बेजोस
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है-28 फरवरी
- जिस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किये जाने की घोषणा की गई है- रियलमी
- ओएनजीसी और एचपीएल ने जिस कंपनी में 34.56 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है- पेट्रोनेट
- वह देश जिसने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए 'बतख-दल' भेजने की घोषणा की है- चीन
- जिसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाये जाने की घोषणा की गई है- एस एन श्रीवास्तव
- हाल ही में जिस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुया सालमिनिकोला की खोज की- इजराइल
- वह उच्च न्यायालय जिसने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है- केरल उच्च न्यायालय
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' की स्थापना को मंजूरी दी है-1,480 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए- म्यांमार
- उत्तर प्रदेश सरकार 'ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय' का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की है- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
- अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है-21 फरवरी
- हाल ही में जिस देश ने 'फूड प्लेनेट प्राइज' नाम से 1 मिलियन डालर के पुरस्कार की घोषणा की है- स्वीडन
- भारत और जिस देश ने भारतीय क्षेत्र के संपदा कामगारों के लिये श्रीलंका के कृषि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं- श्रीलंका
- हाल ही में जिसे देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है- संजय कोठारी
- अमेरिका, जिस देश को पछाड़ कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है- चीन
- वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 के मुताबिक, विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के जितने शहर इसमें शामिल है-21
- वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया- मिस्र
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया- नई दिल्ली
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गुजरात स्थित मोटरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया गया -नमस्ते ट्रम्प

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- शिमला के जुब्बल का महल एक फ्रेंच वास्तुकार द्वारा कब डिजाइन किया गया था- 1930 में
- लकड़ियों के बर्तनों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है- गद्दी
- वजीर फतह राम के कौशल को लेकर गाए जाने वाले गीत का संबंध कौन से स्थान से है- रामपुर बुशहर
- रिवाल्सर में बनी बौद्ध मोनास्ट्री किस शैली में बनाई गई है- पैगोड़ा शैली
- मंडी में जिस स्थान पर देवताओं और जोगिनों की प्रसिद्ध लड़ाई होती है -कांबागिर
- हिमाचल की प्रादेशिक वास्तुकला को किस नाम से जाना जाता है- काठकुणी
- हिमाचल का राज्य संग्रहालय कब खोला गया -1974 में
- बोनीमून, जहां पूर्व में संग्रहालय स्थापित था, का निर्माण किसने किया था- राबर्ट टाइटलर
- चंदू लाल रैना का संबंध किस कला से है - चित्रकला से
- हिमाचल प्रदेश जल विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश में किस अनुपात से खर्चा किया जाएगा- 90 अनुपात 10
- जल विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र परियोजना के लिए हिमाचल को किस द्वारा सहायता दी जा रही है- विश्व बैंक
- शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था- वर्ष 1964 में
- हिमाचल के किस जिला में गुड-फूड, गुड-मूड अभियान स्वच्छ व साफ खाद्य उपलब्ध करवाने के लिए चलाया - मंडी
- मंडी जिला के बल्ह तहसील के चक्कर नामक स्थान पर इंडो जर्मन दूध प्रोसेसिंग प्लांट कब स्थापित किया गया था- वर्ष 1960
- हाल ही में हिमाचल विधानसभा का अध्यक्ष कौन है -विपिन सिंह परमार
- हिमाचली के किस लेखक को साहित्य रत्न सम्मान से दिया गया है - कवि प्रमोद कुमार, सरकाघाट
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी हुए पर्फोमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल ने कौन सा रैंक प्राप्त किया है- 6वां रैंक
- हाल ही में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कौन सी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं- स्कूल चौथी से नौंवी कक्षा तक
- आगामी वित्त वर्ष के लिए हिमाचल सरकार में प्रमुख प्राथकिता वाला क्षेत्र कौन सा है- सामाजिक क्षेत्र
- आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक योजना में हिमाचल सरकार के 10 जगह अब कितने प्राथमिक सेक्टर होंगे- 11
- चौहार घाटी के प्रमुख देवता हुरंग नारायण के वजीर किस देवता को माना जाता है- पशाकोट देव
- सराज स्थित विष्णु मतलोड़ा किस भगवान का प्रतिरूप माना जाता है- भगवान विष्णु
- हाल ही में मंडी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्री मेले के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर किस खास शब्द का इस्तेमाल किया गया- न्यूद्रा
- हिमाचल में खेल नीति में किस खेल को खेल नीति पर शामिल करने का प्रस्ताव है- पैराग्लाइडिंग
- नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स करनाल ने हिमाचल के किस पशु को हिमाचल पहाड़ी नस्ल के नाम से पंजीकृत किया- हिमाचली पहाड़ी गाय
- अंतरराष्ट्रीय शिवरात्री मेले में देवताओं के नजराने में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई -10 प्रतिशत
- किस राज्य में पैराग्लाइडिंग प्रि वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है- हिमाचल में
- हाल ही में हिमाचल का पहला खुला शौच मुक्त प्लस शहर बना है- शिमला
- मरीची वज्रवाही कहां पर है- लाहौल

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही दो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि योजनाओं के लिए क्या पात्रता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं। पहले इस योजना के तहत 25,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।

ये हैं पात्र

अनाथ लड़कियों, नारी निकेतन, बालिका आश्रम में रहने वाली लड़कियों, तलाकशुदा और तलाकशुदा दंपति की लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। नियमों के तहत कन्यादान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित लड़कियां पंचायत, स्थानीय निकाय, बाल कल्याण परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन, नारी निकेतन और अधीक्षक बाल आश्रम के पास आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र की जिला परियोजना अधिकारी से पुष्टि की जाएगी।

जरुरी दस्तावेज

आवेदन में जन्मतिथि का सुबूत, जिस लड़के से शादी हो रही है, उसका पूरा ब्योरा, शादी की तारीख की स्थानीय स्तर से पुष्टि, आय के प्रमाणपत्र भी देने होंगे। सभी आवेदनों की पूरी जांच होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी की ओर से कन्यादान राशि जारी की जाएगी।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के लाभ

- यह योजना पात्र लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत 40,000 रूपये की वित्तीय सहायता लाभार्थी लड़कियों को उनकी शादी के लिए प्रदान की जाती है।

आवश्यक पात्रता और शर्त

- योजना हिमाचल प्रदेश की निवासी लड़कियों के लिए है।
- लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनका पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट है, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

गूगल पर एचपी वूमैन एंड चाइल्ड वैल्फेयर डिपार्टमेंट का लिंक डालते ही विभाग की योजना जान सकते हैं।

यहां पर डाउनलोड लिंक पर जाकर योजना फार्म डाउनलोड किया जा सकता है।

इस योजना के लिए आप हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं।

योजना का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी जानकारी ले सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आप जिला कार्यालय के पास संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पुनः–विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुनः–विवाह में मदद करना और विधवाओं के साथ पुनर्विवाह करने के लिए पुरुषो को प्रोत्साहित करना है। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 50, 000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 20,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 30,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। पहले इस योजना के तहत भी 25 हजार देने का ही प्रावधान था लेकिन बाद में योजना नियमों संशोधन कर राशि को दोगुना कर दिया गया।

इस पहल ने राज्य के कई असहाय विधवाओं की मदद की है। हिमाचल की सभी विधवा स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक विवरण और आवेदन फार्म निकटतम जिला कल्याण कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, में प्राप्त किया जा सकता है।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ

यह योजना पात्र विधवा को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 25,000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 10,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन विवाह करने के छह माह के भीतर करना अनिवार्य है। इसके लिए योग्यता की पुष्टि करनी भी जरूरी है और जिला या तहसिल कल्याण कार्यालय में आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

- http://himachal.nic.in/index1.php?

आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी ही कार्यालय में जमा करें। आवेदन उनकी शादी के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

आवश्यक पात्रता और शर्त

महिला और पुरुष दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए ।

पुरुष की उम्र 21 से कम न हो
महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम न हो
आवश्यक दस्तावेज
पासपोर्ट आकार का फोटो
बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
पहचान प्रमाण
पुरुष और महिला दोनों के निवासी प्रमाण
आधार कार्ड
विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम और पता
फिर से पुनर्विवाह की तिथि
पहली शादी की तिथि
वह तिथि जब वह विधवा हो गई

मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा महिलाओं, विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके पालन–पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। सरकार ने इसके लिए पात्रता और नियम तय किए हैं।

पात्रता

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की निःसहाय महिलांए

विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं,

महिलाएं जिनके पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में उनके न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हों, या

इस श्रेणी की महिलाएं यदि गरीबी रेखा से नीचे न हों तो परिवार की वार्षिक 35000 रूपये तक होना अनिवार्य है

जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हों

सहायता राशि

दो बच्चों तक प्रति वर्ष 3000 रूपये प्रति बच्चा 18 वर्ष तक की आयु तक।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय मे जमा करें:

आय का प्रमाण पत्र,

पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र,

हिमाचली प्रमाण पत्र,

परिवार रजिस्टर की नकल,

आधार कार्ड की छायाप्रति,

ग्राम सभा का प्रस्ताव,

आवेदन पत्र, फार्म पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सोलर चरखा मिशन ..... रोजगार के क्षेत्र में नया क़दम

सोलर चरखा मिशन योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोलर चरखा मिशन योजन की शुरुआत की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है । गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शिल्पकार भी है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिल कर कई कदम उठाये हैं। सोलर चरखा मिशन एक ऐसी ही योजना है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे कपड़ों का निर्माण कर अपनी बेहतर आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें। इस योजना के अंतर्गत पहले 2 वर्षों में कुल 550 करोड रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी। जिससे देश में करीब 5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना द्वारा एक लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां प्राप्त करने का

अवसर मिलेगा

सोलर चरखा मिशन से खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य है इस योजना से 5 करोड़ भारतीय महिलाओं को जोड़ना। इस बड़ी योजना के द्वारा एक लाख से ज्यादा नौकरियों का अवसर लोगों को मिलेगा। सोलर चरखा मिशन को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और 50 क्लस्टर में 550 करोड़ रुपए भी इस योजना में सब्सिडी के लिए स्वीकृति दिया जा चुका। हर एक क्लस्टर में लगभग 400 से 2000 कारीगर काम करेंगे। सरकार के अनुसार सोलर चरखा मिशन में लगभग 10000 करोड़ रुपए मात्र छोटे कंपनी सेक्टर में खर्च होने वाले हैं। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक बेहतरीन पहल है। इसके लिए 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किए जाएंगे जिनमें से 10 को इसी वर्ष शुरू करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। यहां सेंटर सभी छोटे उद्यमियों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

सोलर चरखा मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके कौशल के आधार पर नौकरी दिलाना।
- एक प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण का मॉडल बनाना है।
- खादी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।
- हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- गरीब लोगों के लिए स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

सोलर चरखा योजना का उद्देश्य

- देश के पारंपरिक कला से सम्बंधित कुटीर, लघु एवं माध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है।
- सोलर चरखा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत के प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना से महिला उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करना है।
- खादी उद्योग में सूत कातने का काम ज्यादातर महिलाएं करतीं हैं। अतः सोलर चरखा के द्वारा सूत कम समय में ज्यादा तैयार होगें। जिससे देश की महिलाएं की आय में वृद्धि होगी और वो स्वावलंबी बनेंगी।
- इस योजना के तहत सोलर चरखा के माध्यम से सूत तैयार करने में कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा। पारम्परिक चरखे से बुनकर मजदूर दिन में 8 घंटे काम करने पर रूपए 160 कमाते हैं। वहीं सोलर चरखे के द्वारा दिन में रूपए 360 तक कमा पाएंगे। इस तरह उनके आमदनी में वृद्धि होगी।
- इस योजना का उद्देश्य बुनकर-शिल्पकार-सूत कातने वाले मजदूरों के आय में वृद्धि करना, तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- खादी उद्योग को पुनर्जीवित करना है।

सोलर चरखा योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
- सोलर चरखा योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा के उपयोग से नागरिकों को परिचित करवाना है।
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु सोलर ऊर्जा को देश में बढ़ावा देन है।
- सोलर चरखा के उपयोग से बुनकरों और सूत कातने वाले मजदूरों की आय में वृद्धि करना है।
- इस योजना के माध्यम से देश भर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, तथा प्रत्येक पंचायत में 1100 नए रोजगार का सृजन होगा ।

सोलर चरखा योजना का बिजनेस मॉडल

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिए जायेगा। इस योजना के तहत सोलर ऊर्जा इकाई स्थापित करने का कुल खर्च 24,87,694/- रूपए है । इसमें से रुपये 22,38,925/ लोन बैंक से प्राप्त हो जायेगा, तथा बची हुई राशि का(मार्जिन मनी) रूपए 621924/ सब्सिडी सरकार की ओर से स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के एवज में PMEG के अंतर्गत मिलेगा। आपको अपने पास से लगाना है मात्र रूपए 248769/ और आपका सोलर चरखा प्रोजेक्ट लग जायेगा। इस उद्यम को लगाकर आप वार्षिक 80,000– 100000 रूपए तक कम सकेंगे ।

सौर चरखा मिशन के बारे में:

- सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंगे।
- यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं।
- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा।
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है।
- इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा।
- सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
- सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है।
- इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख महिलाओं को नौकरियां देगी।
- सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा।
- इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा है। केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।
- एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है।

ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदाम

खाद्यान्नों के सहज और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदामों का एक नेटवर्क आवश्यक है। वर्तमान में, कई राज्यों में एफसीआई की भंडारण डिपुओं से खाद्यान्न उठाए जाते हैं और उचित दर दुकानों को सीधे भेज दिए जाते हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मध्यवर्ती स्तर पर भंडारण सुविधाओं, जहां से खाद्यान्न उचित दर दुकानों तक भेजा जा सकता है, के निर्माण की जरूरत पर समय-समय पर राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है। पंचायत स्तर पर निर्मित इस तरह का गोदाम किसानों को अपनी फसलों को बेचने, स्टॉफ रखने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

ऐसे गोदामों का निर्माण अब राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत प्रदान की गई निधि का उपयोग कर किया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में उपयुक्त संशोधन कर दिया है जिसके परिणामस्वीरूप इस तरह के निर्माण योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों में शामिल हो गया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अमेरिका और ब्रिटेन से भी शानदार है भारत का ये ट्रंप टावर, एक फ्लैट की कीमत है 15 करोड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इससे पहले वो एक सफल रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। उनका निजी निवास स्थान मैनहैटन का ट्रंप टावर है। इसी की तर्ज पर भारत सहित दुनियाभर के कई देशों में भी ट्रंप टावर बनाए गए हैं। इनमें से एक ट्रंप टावर तो ऐसा है जो अमेरिका और ब्रिटेन से भी शानदार और आलीशान माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां महज एक फ्लैट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। यह ट्रंप टावर पुणे के कल्याणी नगर में बना है, जिसका उद्घाटन डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने साल 2018 में किया था। यह ट्रंप टावर भारत की रियल एस्टेट कंपनी पंचशील डेवलपर्स के सहयोग से बना है। पंचशील ग्रुप के चेयरमैन अतुल चोरडिया के मुताबिक, 23 मंजिला ये ट्रंप टावर सबसे आलीशान और देश की पहली इको फ्रेंडली इमारत है। इस ट्रंप टावर में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, उनके बेटे रणबीर कपूर से लेकर कैटरीना कैफ तक के फ्लैट्स हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने भी यहां करीब 16 करोड़ रुपये का एक पेंटहाउस खरीदा है। 23 मंजिला इस ट्रंप टावर की खासियत ये है कि इसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से कांच से बना हुआ है। हर मंजिल पर 6100 स्क्वेयर फुट का एक फ्लैट है। इनमें मॉडर्न फिटनेस सेंटर भी हैं। हर फ्लैट में आउटडोर स्विमिंग पूल है। इसके अलावा यहां के फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ बायोमेट्रिक कार्ड

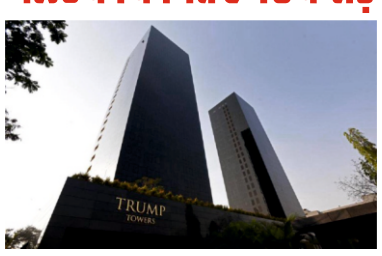

के जरिए ही फ्लैट के अंदर आप एंट्री होगी। इस ट्रंप टावर में वर्ल्ड क्लास स्पा भी है, जबकि सुरक्षा के लिए इमारत में वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि यह ट्रंप टावर विवादों में भी रह चुका है। आरटीआई कार्यकर्ता रवि बराहते ने इमारत बनाने में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसकी जांच महाराष्ट्र के राजस्व विभाग की ओर से हुई थी, लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाया था।

आखिर क्यों अमेरिका ने नागासाकी पर गिराया था परमाणु बम? हैरान कर देगी वजह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

छह अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। बताया गया कि परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई। एक झटके में हजारों लोगों की मौत हो गई। इससे होने वाली नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, उससे पहले ही जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। नागासाकी पर नौ अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराया गया। हालांकि नागासाकी पर परमाणु हमला तय नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह शहर निशाना बन गया?

आठ अगस्त, 1945 की रात बीत चुकी थी, अमेरिका के बमवर्षक बी-29 सुपरफोर्ट्रेस बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी भीमकाय तरबूज-सा था और वजन था 4050 किलो। बम का नाम विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन रखा गया। इस दूसरे बम के निशाने पर था औद्योगिक नगर कोकुरा। यहां जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला-बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थीं। सुबह नौ बजकर पचास मिनट पर नीचे कोकुरा नगर नजर आने लगा। इस समय बी-29 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा

था। बम इसी ऊंचाई से गिराया जाना था, लेकिन नगर के ऊपर बादलों का डेरा था। बी-29 फिर से घूम कर कोकुरा पर आ गया। लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुंए का कब्जा था और नीचे से विमान-भेदी तोपें आग उगल रहीं थीं। बी-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस पहुंच सकें। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया, हमने सुबह नौ बजे उड़ान शुरू की। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इसे छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद भीमकाय बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकेंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी तल से 500 फुट की उंचाई पर फट गया। घड़ी में समय था 11 बजकर 2 मिनट। आग का एक भीमकाय गोला मशरुम की शक्ल में उठा। गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहर को निगलने लगा। नागासाकी के समुद्र तट पर तैरती नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आस पास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह जान ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुके थे। शहर के बाहर कुछ ब्रितानी युद्धबंदी खदानों मे काम कर रहे थे, उनमें से एक ने बताया, पूरा शहर निर्जन हो चुका था, सन्नाटा। हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थी। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ-पैर गल रहे थे, हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। बाद के अनुमानों में बताया गया कि हिरोशिमा में एक लाख 40 हजार लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में हुए धमाके में करीब 74 हजार लोगों की मौत हुई।

अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहने के पीछे है 118 साल पुराना इतिहास

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया के लगभग हर देश में राष्ट्रपतियों के रहने के लिए एक आधिकारिक आवास बनाया गया है। भारत में तो इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। हालांकि हमेशा से इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ था, तब इसका नाम प्रेसीडेंट्स पैलेस या प्रेसीडेंट मैंशन था। इसके बावजूद इसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया। दरअसल, इसके पीछे 118 साल पुराना इतिहास छुपा हुआ है। आयरलैंड में पैदा हुए जेम्स होबन ने व्हाइट हाउस का डिजाइन तैयार किया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1792 से 1800 के बीच यानी आठ साल में पूरा हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज व्हाइट हाउस जहां पर खड़ा है, वहां पर कभी जंगल और पहाड़ थे। व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 अंगीठी, 8 सीढ़ियां और तीन लिफ्ट भी हैं। छह मंजिला इस इमारत में दो बेसमेंट, दो पब्लिक फ्लोर और बाकी के फ्लोर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस में पांच फुलटाइम शेफ काम करते हैं और भवन के अंदर 140 मेहमानों के एकसाथ रात्रि भोजन की व्यवस्था है।

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे कहानी ये है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वाशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी। इसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई, जिसके बाद इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही इसे 'व्हाइट हाउस' कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाउस हाउस ही रख दिया।

लग्जम्बर्ग में इसी माह से ट्रेन या बसों में आना-जाना सबके लिए होगा मुफ्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दिल्ली में महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में सफर करना मुफ्त है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जो अगले महीने से सभी नागरिकों के लिए ट्रेन या बसों में आना-जाना मुफ्त कर देगा। आपको यह जानकर हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। ऐसा करने वाला यह देश दुनिया का पहले देश होगा। इस देश का नाम है लग्जमबर्ग, जो यूरोप का सातवां सबसे छोटा लेकिन अमीर देश है। यहां एक मार्च 2020 से ट्रेन, ट्राम और बसों में आने-जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। देश के नागरिकों के लिए परिवहन की ये सारी सुविधाएं मुफ्त होंगी और सिर्फ देश के नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि इससे लग्जमबर्ग में आने वाले सैलानियों का भी फायदा होगा।

दरअसल, साल 2018 के अंत में जेवियर बेटल ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये एलान किया था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से लक्जमबर्ग के करीब छह लाख निवासियों, 1,75,000 सीमा-पार के मजदूरों और यहां

आने वाले सालाना 12 लाख सैलानियों को फायदा होगा। लक्जमबर्ग में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने के पीछे भीड़भाड़ कम करना या पर्यावरण की दशा सुधारना मुख्य मकसद है। इसके अलावा इसका मकसद अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को भी पाटना है। दरअसल, यूरोपीय संघ के सभी देशों के मुकाबले यहां प्रति व्यक्ति कारों की संख्या सबसे ज्यादा है। लक्जमबर्ग में 60 फीसदी से अधिक लोग दफ्तर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 19 फीसदी लोग ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि लक्जमबर्ग में सार्वजनिक परिवहन पर पहले से भारी सब्सिडी है। दो घंटे के सफर की कीमत यहां दो यूरो यानी करीब 155 रुपये और पूरे दिन के लिए सेकेंड क्लास टिकट की कीमत चार यूरो यानी करीब 312 रुपये है। लेकिन 20 साल तक के छात्र-छात्राओं के लिए यहां सरकार ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रखी है।

दुनिया का सबसे अनोखा नाइट क्लब, जहां संस्कृत गीतों पर थिरकते हैं लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में आमतौर पर नाइट क्लबों में हिंदी, पंजाबी या फिर अंग्रेजी गाने बजते हैं, जिसपर लोग थिरकते नजर आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से दूर दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां एक अनोखा नाइट क्लब है। इस नाइट क्लब में संस्कृत गीतों पर लोग थिरकते नजर आते हैं। इस देश का नाम है अर्जेंटीना, जहां की राजधानी ब्यूनस-आयर्स में ग्रोव नाम का एक नाइट क्लब है। यहां गणेश शरणम, गोविंदा-गोविंदा, जय-जय राधा रमन हरी बोल और जय कृष्णा हरे जैसे गीत बजते हैं। ब्यूनस-आयर्स का यह नाइट क्लब कोई छोटा-मोटा नाइट क्लब नहीं है, बल्कि यहां एक साथ करीब 800 लोग गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। दरअसल, एक भारतीय राजनयिक विश्वनाथन साल 2012 में अर्जेंटीना गए थे और उन्होंने ही अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया कि उस नाइट क्लब में न तो शराब मिलती है और न ही लोग धूम्रपान करते नजर आते हैं। यहां तक की इस नाइट क्लब में ड्रग्स की भी मनाही है और मांस-मछली भी नहीं मिलता। यहां सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स, फलों का रस और शाकाहारी खाना ही मिलता है।

पाकिस्तान के इस हिंदू मंदिर में मुसलमान भी टेकते हैं मत्था

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत की पहचान विभिन्न कड़ियों से होती है, फिर चाहे बात यहां की विविधता की हो या फिर इसके सांस्कृतिक इतिहास की। यह तो सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरातन है, जिसका दायरा हिमालय के बर्फ से लेकर दक्षिण के श्रीलंका तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक फैला है। इतना ही नहीं भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरे विश्व में मशहूर हैं। इन मंदिरों में रोजना लाखों की मात्रा में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने जाते हैं। हालांकि मंदिरों में केवल हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है, जहां हिंदू ही नहीं मुस्लिम लोग भी पूजा करने जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह जिसके चलते उस मंदिर में मुस्लिम लोग भी मत्था टेकते हैं?

52 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित इस पवित्र मंदिर में हिंगलाज माता की पूजा की जाती है। बात अगर हम इसके इतिहास की करें तो यह कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती की लाश अपने गोद में लिए थे, उस समय विष्णु भगवान ने सती माता का सिर काटने के लिए चक्र फेंका था। उस चक्र ने सीधे जाकर सती माता का सिर काट दिया। कटने के बाद सिर सीधे आकर पृथ्वी पर गिरा। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर माता का सिर इसी जगह पर गिरा था। बाद में इसे हिंगलाज माता के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से 120 किलोमीटर की दूरी पर हिंगुल नदी के तट पर स्थित है। माता के 52 शक्तिपीठों में इस जगह का नाम भी आता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी ने इस पवित्र मंदिर में कई बार लूट-पाट की थी। इस बात का जिक्र 1500 साल पहले घूमने आए चीनी बौद्ध भिक्षुओं के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। स्वामी नारायण मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर के बंदर रोड पर स्थित है। ये मंदिर करीब 32,306 हजार स्कवेयर यार्ड में बना हुआ है। यह मंदिर लगभग 160 साल पुराना है। जितनी आस्था के साथ इस मंदिर में हिन्दु मत्था टेकते हैं उतनी ही आस्था के साथ यहां मुस्लमान भी मत्था टेकते हैं। यही नहीं जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस दौरान इस हिंदू मंदिर का उपयोग रिफ्यूजी कैंप के रूप में भी किया गया था। वही ये मंदिर गंगा जमुनी तहजीब के तहत प्रेम का संदेश देती है। वहीं कराची स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि यह मंदिर तकरीबन 2000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित एक हनुमान जी के मूर्ति को त्रेतायुग से भी 17 लाख साल पुराना माना जाता है। इसका पुनर्निर्माण साल 1082 में कराया गया था। भारत के लोगों की राम जी में गहरी आस्था के कारण यहां अनेकों राम मंदिर हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ राम मंदिर स्थित हैं जिनमें सबसे विशेष इस्लाम कोट का राम मंदिर है।

द रीव टाइम्स
स्वामी/ संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा
प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.
द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
संपादक: हेम राज चौहान
फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021
E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना
हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स
दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org